RNI No. : TNHIN/2013/52522 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 188 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- ▪ चेन्नई » मंगलवार » 03-02-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा : योगी

6 नारी देह, नारी अधिकार: माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

7 फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं : शुभांगी अत्रे

फर्स्ट टेक

इसरो जून में पीएसएलवी के प्रक्षेपण का प्रयास करेगा : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि दो लगातार असफलताओं के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जून में अपने प्रमुख रॉकेट पीएसएलवी का एक और प्रक्षेपण करेगा। सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पीएसएलवी–सी61 और सीएसएलवी–सी62 मिशनों के क्रमश: मई 2025 और जनवरी 2026 में असफल होने के कारण एक जैसे नहीं थे। सिंह ने 'पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल' (पीएसएलवी) की दो लगातार असफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा, पिछली बार जो हुआ, वह इस बार नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, हमारी अगली संभावित तिथि जून में है।

जापान ने समुद्र तल से दुर्लभ खनिज प्राप्त करने के लिए अभियान शुरू किया

टोक्यो/एपी। जापान ने सोमवार को कहा कि उसने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एक दूरस्थ द्वीप के पास समुद्र तल से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने 'एक्स' पर एक बयान में कहा कि गहरे समुद्र में ड्रिलिंग में सहायक पोत चिक्यू की मदद से मिनमितोरिशिमा द्वीप के पास अतल गहराई पर इस काम को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इतनी गहराई से दुर्लभ खनिजों का परीक्षण करके निकालना विश्व में अपनी तरह का पहला प्रयास है। ताकाइची ने कहा, यह जापान में घरेलू स्तर पर उत्पादित दुर्लभ खनिजों के औद्योगीकरण की दिशा में पहला कदम है। हम दुर्लभ खनिजों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला स्थापित करने का प्रयास करेंगे ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके।

ब्रिटेन ने पलटवार करते हुए रूसी राजनयिक को निष्कासित किया

लंदन/एपी। ब्रिटेन ने पिछले महीने जासूसी के आरोपों में ब्रिटिश राजनयिक को रूस से निष्कासित किए जाने के मामले में पलटवार करते हुए रूसी राजनयिक को अपने देश से निष्कासित कर दिया है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने सोमवार को बताया कि उसने रूस के राजदूत एंड्रे केलिन को तलब करके ब्रिटिश दूतावास के कर्मचारी के खिलाफ रूस के अनुचित फैसले और निराधार आरोपों की निंदा की। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा, यह बहुत की निराशाजनक है कि रूस ब्रिटेन के राजनयिक मिशन के कामकाज में लगातार बाधा डालने और यूक्रेन के प्रति हमारे समर्थन को रोकने की कोशिश कर रहा है।

03-02-2026 सूर्यास्त 6:10 बजे | 04-02-2026 सूर्योदय 6:34 बजे

BSE	NSE
81,666.46	25,088.40
(+943.52)	(+262.95)

सोना	चांदी
15,434 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	267,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

चत्वारि कालखण्ड

सतयुग से त्रेता युग तक था,
सच्चे लक्षण का कालखण्ड।
द्वापर से कलयुग आदि रहा,
हित संरक्षण का कालखण्ड।
आजादी तक का समय रहा,
शोषण भक्षण का कालखण्ड।
नब्बे के दशक बाद का है,
बस आरक्षण का कालखण्ड।।

ट्रंप ने मोदी से फोन पर बातचीत के बाद कहा

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाला जवाबी शुल्क मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यह जानकारी दी। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका के खिलाफ शुल्क और गैर–शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद।'' मोदी ने कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मोदी ने कहा, ''मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं।'' ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मित्रता व उनके प्रति सम्मान के मद्देनजर तथा उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत अमेरिका जवाबी शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा।

अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा : मोदी

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की। इस बातचीत की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद।''

भारत को हर बात ट्रंप से पता चलती है, यह 'ट्रंप-निर्भरता' है : कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब 'ट्रंप–निर्भरता' है क्योंकि भारत को हर बात ट्रंप या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से पता चलती है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने आज एक दूसरे से बात की है। यह जानकारी भारत की ओर से नहीं बल्कि भारत में अमेरिकी राजदूत की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा, ''लगता है कि यह अब नियमित हो गया है कि भारत को अपनी सरकार के कार्यों के बारे में केवल राष्ट्रपति ट्रंप या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों से ही पता चलता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह 'ट्रंप–निर्भरता' है।

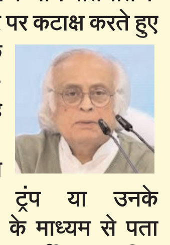

रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता : करंदलाजे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने सोमवार को कहा कि रोजगार सृजन उसकी प्राथमिकता है और देश में रोजगार सृजित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा युवाओं में बेरोजगारी संकट पर पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017–18 के 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 58.2 प्रतिशत हो गया, जो रोजगार बढ़ने का संकेत देता है।

मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन के साथ–साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है और वह देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि 'स्किल इंडिया मिशन' (एसआईएम) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रदान कर रहा है और उनके कौशल को बढ़ा रहा है।

रुपया 44 पैसे बढ़कर 91.49 प्रति डॉलर पर

मुंबई/भाषा। आम बजट 2026–27 पेश होने के एक दिन बाद अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे के सुधार के साथ 91.49 पर बंद हुआ। रुपये में यह बढ़त मुख्य रूप से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों में आई गिरावट के कारण देखी गई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 92 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को बचाने के लिए पूरी मजबूती से सक्रिय नजर आया।

भाजपा का राष्ट्रवाद झूठा : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रवाद को झूठा करार दिया और सवाल किया कि पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि मोदी सरकार के मंत्री घबरा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवालों पर जवाब देने से ऐसे बच रही है जैसे उसकी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो।

खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आरएसएस–भाजपा की वैचारिक आधारशिला ही तथ्यों को छिपाने पर टिकी है, तभी ये कायर मोदी सरकार संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवालों पर जवाब देने से ऐसे बच रही है जैसे उसकी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो।'' उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया, ''पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब में ऐसा क्या लिखा है जिससे मोदी सरकार के बड़े–बड़े मंत्री घबरा रहे हैं? उनकी किताब को प्रकाशित होने से कौन रोक रहा है? ''

खरगे ने दावा किया, ''पूरा देश जानता है कि भाजपा का राष्ट्रवाद झूठा है। वो देशभक्ति की बड़ी–बड़ी बातें करते हैं पर 2020 में गलवान में हमारे 20 जवानों के सर्वोच्च बलिदान के बाद मोदी जी ख़ुद चीन को क्लीन चिट थमा देते हैं। क्या ये सच नहीं है? '' उन्होंने कहा, ''क्या संसद में इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर देश को विश्वास में नहीं लिया गया है? लोकतंत्र की जननी की बात करने वाले लोकतंत्र की आत्मा को रौंदने में क्यों जुटे हुए हैं?''

हिंदू ग्रंथ पाठ

गुजरात के वडोदरा में सोमवार को बीएपीएस प्रमुख महंत स्वामी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर स्वामीनारायण संप्रदाय के श्रद्धालु विश्व के सबसे बड़े एक साथ हिंदू ग्रंथ पाठ के रिकॉर्ड प्रयास में भाग लेते हुए।

यूपीआई के जरिये लेन-देन मुफ्त बना रहेगा : वित्तीय सेवा सचिव

नई दिल्ली/भाषा। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को कहा कि यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) को समर्थन देने को लेकर 2026–27 के बजट में 2,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से इसके जरिये मुफ्त में लेन–देन बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों की गड़बड़ी के कारण साइबर धोखाधड़ी तीन प्रतिशत से भी कम है और लोगों की सतर्कता से इस समस्या से निपटा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में लोकप्रिय डिजिटल भुगतान ऐप यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के लिए 2,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। यह 2025–26 में संशोधित अनुमान के अनुसार 2,196 करोड़ रुपए थी। नागराजू ने यहां संवाददाताओं से कहा, '' यूपीआई को समर्थन देने को लेकर 2026–27 के बजट में 2,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का मतलब है कि इसके जरिये मुफ्त में लेन–देन जारी रहेगा।'' साइबर धोखाधड़ी से जुड़े एक सवाल के जवाब में नागराजू ने कहा, ''बैंकों की गड़बड़ी के कारण साइबर धोखाधड़ी तीन प्रतिशत से भी कम है और लोगों की सतर्कता से इस समस्या से निपटा जा सकता है।''

बांग्लादेशियों का पता लगाने के लिए अभियान चलाएंगे : जी. परमेश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

■ बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने का काम पहले से ही चल रहा है। बांग्लादेशी सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मौजूद हैं।

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि राज्य से बांग्लादेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

परमेश्वर ने विधानसभा में कहा, मैंने पुलिस अधिकारियों को बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। हमें पता चला है कि बांग्लादेशी मुख्य रूप से चिक्कमगलुरु, हसन, बेंगलूरु शहर, बेंगलूरु ग्रामीण और कोडगु में केंद्रित हैं। उनके अनुसार, बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने का काम पहले से ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मौजूद हैं।

भारत में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत में प्रवेश करते हैं और कोलकाता से फैल जाते हैं। उन्होंने कहा, भारतीय सीमा की देखरेख कौन करता है? हमारी सेना और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)। वे इतनी आसानी से देश में प्रवेश कैसे कर लेते हैं? क्या यह सबसे बुनियादी सवाल नहीं है?

कर्नाटक में लाखों अवैध बांग्लादेशियों के होने के दावे को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार उन्हें खुलेआम घूमने नहीं देगी। मंत्री ने कहा कि 2021 में जब भाजपा सत्ता में थी, तब 15 लोगों को निर्वासित किया गया था और 2022 में 21 लोगों को।

कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद, 2023 में 47 लोगों को, 2024 में 62 लोगों को और 2025 में 87 लोगों को निर्वासित किया गया।

परमेश्वर ने सदन को बताया, हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद 196 लोगों को निर्वासित किया गया। हमने 370 लोगों की पहचान कर ली है। उनके खिलाफ विभिन्न मामले लंबित हैं, इसलिए हमने उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

परमेश्वर ने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियां न होने दें।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा

अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर निर्वासित करना सरकार की जिम्मेदारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना सरकार की जिम्मेदारी है।

भागवत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देश अपने–अपने हितों से चलते हैं, भारत को भी बिना किसी समझौते के अपने हितों के अनुसार अपनी राह तय करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना चाहिए।

आरएसएस की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, भागवत ने शहर की अपनी यात्रा के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को आयोजित 'संघ यात्रा के 100 वर्ष – नए क्षितिज' विषय पर एक कार्यक्रम में शिरकत की और फिल्मी हस्तियों तथा वरिष्ठ नौकरशाहों से मुलाकात की।

देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना सरकार की जिम्मेदारी है और नागरिक इसे अधिकारियों के संज्ञान में ला सकते हैं।

भागवत ने कहा कि दुनिया में जारी उथल–पुथल के परिणामों का भारत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहां की पारिवारिक व्यवस्था, सोने की बचत और आर्थिक गतिविधियां परिवार–उन्मुख हैं।

अंतरिक्ष से आ रहे रहस्यमय धीमे रेडियो संकेतों की गुत्थी जल्द सुलझ सकती है

■ अध्ययन के अनुसार, अब तक का सबसे लंबे समय तक सक्रिय लॉन्ग-पीरियड ट्रांज़िएंट जीपीएम जे1839-10 है जो वास्तव में एक 'व्हाइट ड्वार्फ' तारा हो सकता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पर्थ/द कन्वरसेशन। अंतरिक्ष से हर कुछ मिनटों या घंटों में दोहराए जाने वाले रहस्यमय रेडियो संकेत ''लॉन्ग–पीरियड ट्रांज़िएंट्स'' की खोज 2022 में हुई थी लेकिन इनके बारे में तब अधिक जानकारी नहीं मिल पाई और खगोलविद इनका रहस्य सुलझाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे।

'नेचर एस्ट्रोनॉमी' में प्रकाशित एक नए अध्ययन में इन संकेतों की प्रकृति को लेकर अहम जानकारी सामने आई है।

रेडियो खगोलविद 'पल्सर' से भली–भांति परिचित हैं, जो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। पृथ्वी से देखने पर ये इसलिए स्पंदित दिखाई देते हैं क्योंकि इनके ध्रुवों से निकलने वाली शक्तिशाली रेडियो किरणें लाइटहाउस की तरह अंतरिक्ष में घूमती हैं। अब तक ज्ञात सबसे धीमे पल्सर भी कुछ सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं।

हाल के वर्षों में ऐसे रेडियो संकेतों के स्रोत खोजे गए हैं, जिनकी अवधि 18 मिनट से लेकर छह घंटे से अधिक तक है। मौजूदा भौतिकी के अनुसार, न्यूट्रॉन तारे इतनी धीमी गति से घूमते हुए रेडियो तरंगें उत्पन्न नहीं कर सकते, जिससे वैज्ञानिकों के सामने नई पहेली खड़ी हो गई।

अध्ययन के अनुसार, अब तक का सबसे लंबे समय तक सक्रिय लॉन्ग–पीरियड ट्रांज़िएंट जीपीएम जे1839–10 है जो वास्तव में एक 'व्हाइट ड्वार्फ' तारा हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह तारा अपने एक सहचर तारे की मदद से शक्तिशाली रेडियो किरणें उत्पन्न कर रहा है, और संभव है कि अन्य ऐसे स्रोत भी इसी तरह के हों।

'व्हाइट ड्वार्फ' मृत तारों के अवशेष होते हैं, जो आकार में पृथ्वी जितने लेकिन द्रव्यमान में सूर्य के बराबर होते हैं। अकेले व्हाइट ड्वार्फ से अब तक रेडियो स्पंदन नहीं देखे गए हैं, लेकिन जब वे किसी एम–टाइप ड्वार्फ तारे के साथ द्वितारा प्रणाली में होते हैं, तो ऐसी गतिविधि संभव हो जाती है। वर्ष 2016 में पहले व्हाइट ड्वार्फ पल्सर की पुष्टि हो चुकी है। अब तक खोजे गए दस से अधिक लॉन्ग–पीरियड ट्रांज़िएंट्स में से 2025 में पहली बार दो को निश्चित रूप से व्हाइट ड्वार्फ एम–ड्वार्फ द्वितारा प्रणाली के रूप में पहचाना गया, जिसने वैज्ञानिकों को नए सवालों पर विचार करने के लिए मजबूर किया।

वर्ष 2023 में खोजे गए जीपीएम जे1839–10 की परिक्रमा अवधि 21 मिनट है और यह अन्य स्रोतों की तुलना में असाधारण रूप से लंबे समय से सक्रिय पाया गया।

आठ राज्यों में समुद्र तट की रेत में एक करोड़ 31.5 लाख टन मोनाज़ाइट का अनुमान : रेड्डी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक इकाई, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने समुद्र तट की रेत और कठोर चट्टानों में महत्वपूर्ण दुर्लभ धातु खनिज संसाधनों का अनुमान लगाया है, जिसके अंतर्गत आठ राज्यों के भंडारों में एक करोड़ 31.5 लाख टन मोनाज़ाइट की पहचान की गई है। मोनाज़ाइट एक लाल-भूरा, फॉस्फेट खनिज है जो दुर्लभ-धातु तत्वों (आरईई) और थोरियम से भरपूर है। यह मुख्य रूप से समुद्र तट की रेत और आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है।

कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''28 जनवरी, 2026 तक, एएमडी द्वारा अनुमानित दुर्लभ धातु खनिज संसाधनों में समुद्र तट खनिज के 136 भंडार शामिल हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तटीय समुद्र तट, टेरी अथवा लाल रेत और आंतरिक एल्युवियम में पाए जाने वाले एक करोड़ 31.5 लाख टन मोनाज़ाइट (थोरियम और दुर्लभ धातु का एक खनिज) शामिल है।''

इन भंडारों में लगभग 72.3 लाख टन इन-सीटू दुर्लभ धातु ऑक्साइड (समकक्ष) संसाधन हैं, जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तटीय समुद्र तट, टेरी/लाल रेत और आंतरिक एल्युवियम में मौजूद हैं। रेड्डी ने कहा कि इसके अतिरिक्त, एएमडी ने राजस्थान और गुजरात में कठोर चट्टानों में दुर्लभ-धातु खनिजों के तीन भंडारों की पहचान की है, जिनमें 12.9 लाख टन इन-सीटू आरईओ संसाधन हैं।

मोनाज़ाइट अपने रेडियोधर्मी तत्वों यूरेनियम और थोरियम से जुड़ाव के कारण एक निर्दिष्ट पदार्थ है, जिससे खनन, प्रसंस्करण और शोधन सख्त सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत आता है।

भारत दुनिया के उन तीन से चार देशों में से एक है जिसके पास दुर्लभ-धातु क्षेत्र में संयंत्र, प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल के मामले में क्षमता और काबिलियत है।

चांदी 52,000 रुपए और टूटी, सोना 12,800 रुपए कमजोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। चांदी की कीमतें लगातार तीसरे दिन तेजी से गिरीं। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में यह 52,000 रुपए टूटकर 2.60 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जबकि कमजोर वैश्विक रुझानों और मजबूत डॉलर के बीच सोना टूटकर 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 52,000 रुपए, या लगभग 17 प्रतिशत टूटकर 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) रह गई।

शनिवार को, चांदी 19 प्रतिशत, या 72,500 रुपए गिरकर 3.12 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रह गई थी।

पिछले तीन सत्रों में, चांदी की कीमतें 1,44,500 रुपए, या लगभग 36 प्रतिशत गिरकर 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर से नीचे आ गई हैं। 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर 29 जनवरी को दर्ज किया गया जो अब तक की सबसे ऊंची कीमत थी।

99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत पर भी बिकवाली का असर पड़ा। सोमवार को यह 12,800 रुपए, या 7.73 प्रतिशत गिरकर 1,52,700 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) रह गया। पिछले सत्र में यह 1,65,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

पिछले तीन सत्रों में, सोना 30,300 रुपए, या लगभग 17 प्रतिशत गिरकर 29 जनवरी के 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गया है, क्योंकि तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की होड़ मच गई।

भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था बताती है कि विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार के प्रयासों से देश में तेज गति से विकास होने का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कहा कि उथल-पुथल के इस दौर में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था बताती है कि विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा।

भाजपा की डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश सर्वोपरि है और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा ''लेकिन जो लोग राष्ट्र हित की गंभीरता को नहीं जानते, उनके लिए सदन में हंगामा करना कोई बड़ी बात नहीं है।'' इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए मनोनीत सी सदानंद मास्टर ने कहा कि पिछले दस वर्षों के शासन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने विकास के कई कदम उठाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर बदली है उससे विश्व भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। सदानंद ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रवाद की प्रेरणा से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए डॉ मेधा ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए ''हमें अथक परिश्रम करना है और आर्थिक समीक्षा बताती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। '' मेघा ने कहा, कि 'उथल-पुथल के इस दौर में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था बताती है कि विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा। उन्होंने कहा '' बीते वर्षों में तीन करोड़ करदाता बढ़े हैं। इसका मतलब है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ी, वह खरीदी कर रहे हैं और कर भी दे रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी रेखा से ऊपर आना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि चार करोड़ से अधिक आवास बनाए गए, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, 56 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला, 20 लाख से अधिक लोग स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। ''यह उपलब्धियां बताती हैं कि मेहनत भी की और मेहनत सफल भी हुई।'' उन्होंने कहा कि 12 करोड़ से अधिक लाभार्थी मुद्रा योजना के हैं जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। ''महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण और क्या होगा।'' डॉ मेधा ने कहा ''आज देश में 55 करोड़ से अधिक जन धन खाते हैं। इन्हें आधार से जोड़ा गया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के चलते पैसा सीधे खातों में गया। कोई हेराफेरी नहीं हुई। पहले की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया ?

सरकार बिना किसी भेदभाव के, सभी राज्यों का ध्यान रखे : विपक्षी सदस्यों ने रास में की मांग

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में सोमवार को अपने अपने राज्यों की समस्याओं के अनसुलझे रहने का दावा करते हुए विपक्ष शासित राज्यों के नेताओं ने कहा कि सरकार को सभी राज्यों का बिना किसी भेदभाव के ध्यान रखना चाहिए और विकास में मदद करना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उच्च सदन में पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले रहे बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने कहा कि ओडिशा में किसान बहुत परेशान हैं। वह अपना धान लेकर मंडी जाते हैं लेकिन उनका धान खरीदा नहीं जाता। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जो एमएसपी देने का वादा किया था, वह नहीं दिया जा रहा। राज्य में महिलाओं व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए खान ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश में ठप हो चुकी है। राज्य में जलविवाद अभी भी अनसुलझा है। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने पोलावरम बांध की ऊंचाई कम करने की मांग की ताकि ओडिशा के गांवों के लोगों की जमीन डूब वाले हिस्से में न जाए।

सरकार अगले वित्त वर्ष में एफपीओ के जरिये एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने पर कर रही विचार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नई दिल्ली/भाषा। सरकार अगले वित्त वर्ष में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) के माध्यम से बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी और घटाने पर विचार कर रही है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को यह जानकारी दी।

वर्तमान में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार ने मई, 2022 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से 902-949 रुपए प्रति शेयर के मूल्य दायरे में कंपनी में 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी।

इस शेयर बिक्री से सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। नागराजू ने संवाददाताओं से कहा, एलआईसी के सार्वजनिक निर्गम को धीरे-धीरे लाना होगा। हमने दीपम (निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग) से एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की संभावनाओं को देखने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा, यदि सभी मंजूरियां मिल जाती हैं और बाजार की स्थिति अनुकूल रहती है, तो अगले वित्त वर्ष में एलआईसी का एफपीओ आ सकता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार, सरकार को मई, 2027 तक इस सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी में 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी और बेचनी होगी। हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा, कीमत और समय के बारे में उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करेगी : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

दिवाला कानून में प्रस्तावित संशोधन समयबद्धता और दक्षता को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। साथ ही भारत की ऋण शोधन व्यवस्था को वैश्विक सर्वोत्तम गतिविधियों के अनुरूप बनाएंगे। उन्होंने लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर रिपोर्ट दे दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रही सीतारमण ने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि कुछ शर्तों के अधीन, समिति के सुझावों को शामिल करते हुए दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक को नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा।'' यह 2016 में लागू हुए आईबीसी अधिनियम का सातवां संशोधन होगा। अंतिम संशोधन 2021 में हुआ था। सरकार ने 12 अगस्त, 2025 को लोकसभा में दिवाला एवं और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया था। इसमें दिवाला समाधान आवेदनों की स्वीकृति में लगने वाले समय को कम करने सहित कई बदलाव के प्रस्ताव किए गए।

कानून व्यवस्था के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

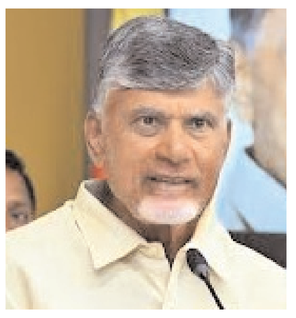

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोपरि है और इसका किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी सप्ताहांत में हुए हंगामे के मद्देनजर आई है, जिसमें गुंटूर में वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता अंबाती रामाबाबू की गिरफ्तारी और विजयवाड़ा में विपक्षी पार्टी के नेता जोगी रमेश के घर पर कथित हमले की घटना शामिल है। नायडू ने एक विज्ञप्ति में कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोपरि है और किसी भी परिस्थिति में, राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना, कोई बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रमेश के आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन की घटना का संज्ञान लिया, जिसके बाद इब्राहिमपटनम पुलिस ने स्वयं ही मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में मैलावराम विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी(तेदेपा) के कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नायडू ने कहा कि कानून का शासन हर समय कायम रहना चाहिए और राजनीतिक मतभेदों को केवल लोकतांत्रिक और संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाना चाहिए। वाईएसआरसीपी द्वारा कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले कार्यों से बचने की अपील की।

वीएसआर वेंचर्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच अंतिम चरण में : एएआईबी

नई दिल्ली/भाषा। विमानन हादसों की जांच करने वाली एजेंसी वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) ने सोमवार को कहा कि मुंबई हवाई अड्डे पर सितंबर 2023 में वीएसआर वेंचर्स के स्वामित्व वाले लियरजेट 45 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच अब अंतिम चरण में है।

महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वह भी वीएसआर वेंचर्स के स्वामित्व वाला 'लियरजेट 45' ही था। इस हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। बारामती विमान हादसे के बाद एएआईबी द्वारा सितंबर 2023 में हुई दुर्घटना पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करने में हुई देरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

वापस आ चुके हैं 2,000 रुपए के 98.42 प्रतिशत नोट: आरबीआई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि 2,000 रुपए के बैंकनोट में से 98.42 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं।

आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी।

रिजर्व बैंक ने बयान में कहा, ''उस समय चलन में मौजूद 2,000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जो 31 जनवरी, 2026 तक घटकर 5,609 करोड़ रुपए रह गया।''

इस तरह 19 मई, 2023 के बाद से चलन में मौजूद 2,000 रुपए के नोटों का 98.42 प्रतिशत वापस जमा हो चुका है।

लोगों के लिए ये नोट जमा करने या अन्य मूल्य वर्ग के नोट से बदलने की सुविधा सभी बैंक शाखाओं में सात अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध थी। उसके बाद से आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालय भी 2,000 रुपए के नोट स्वीकार कर रहे हैं, जिन्हें लोगों के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है।

इसके अलावा, लोग डाकघरों के जरिये आरबीआई के निर्गम कार्यालयों को ये नोट भेजकर अपने खाते में जमा कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने कहा कि ये बैंकनोट वैध मुद्रा बने हुए हैं।

राहुल गांधी ने संसद की गरिमा कम की : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले की अवहेलना करते हुए सदन में भारत-चीन सीमा मुद्दे पर अपने झूठे आरोपों से संसद की गरिमा को कम किया और भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराया।

लोकसभा में उस समय हंगामा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे के एक अप्रकाशित 'संस्मरण' को उद्धृत करने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। हालांकि, रक्षा मंत्री और अन्य भाजपा सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया और कांग्रेस नेता पर सदन को 'गुमराह' करने का आरोप लगाया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के बावजूद इस मुद्दे पर बोलने पर अड़े रहने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना की। उन्होंने 'एक्स' पर कहा, ''यह इन जिद्दी राहुल गांधी के वैचारिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है।'' उन्होंने कहा, ''विदेशी धरती से देश और भारतीय सेना की छवि खराब करने के बाद, राहुल गांधी ने अब संसद के अंदर भी देश को बदनाम करना और भारत के बहादुर सैनिकों का अपमान करना शुरू कर दिया है।'' बलूनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने न केवल संसद की गरिमा को कम किया, बल्कि अपने ''लगातार झूठे आरोपों और गुमराह करने वाले बयानों'' से बहादुर भारतीय सैनिकों का मनोबल भी गिराया। भाजपा सांसद ने कहा, ''राहुल गांधी को कैसे पता चला कि उस किताब में क्या लिखा है जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है? इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मना किए जाने के बावजूद, सदन में बार-बार उसी निराधार दावे को दोहराना न केवल आसन का अपमान है, बल्कि देश और सशस्त्र बलों का भी अपमान है।''

बलूनी ने कहा कि यह ''बेहद दुर्भाग्यपूर्ण'' है कि लोकसभा अध्यक्ष के बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद गांधी बिना किसी सबूत के सदन के पटल से देश को गुमराह कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा, ''पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कई मंचों पर बताया है कि कैसे हमारे बहादुर सैनिकों ने डोकलाम में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।''

सोनम वांगचुक ने नेपाल, बांग्लादेश जैसे प्रदर्शनों के लिए 'जेन जेड' को उकसाने की कोशिश की : केंद्र

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नेपाल और बांग्लादेश की तरह विरोध प्रदर्शन के लिए 'जेन जेड' को उकसाने की कोशिश की थी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.वी. वराले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वांगचुक ने 'अरब स्प्रिंग' जैसे आंदोलन का भी जिक्र किया था। इस आंदोलन के कारण अरब जगत के कई देशों में सरकारें गिर गई थीं। मेहता ने कहा, ''उन्होंने 'जेन जेड' को उकसाने के लिए अपने भाषण को सावधानीपूर्वक तैयार किया और नेपाल और बांग्लादेश की तरह आंदोलन करने का आह्वान किया तथा महात्मा गांधी के भाषणों का इस्तेमाल अपने असली इरादे को छिपाने के लिए किया।'' 'जेन जेड' शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है कि जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। शीर्ष अदालत जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी थी। मेहता ने कहा कि वांगचुक ने केंद्र सरकार को ''वे'' कहकर संबोधित किया और लद्दाख के लोगों को ''हम'' बताते हुए ''जनमत संग्रह'' की मांग की, ठीक वही मांगें जो पहले जम्मू कश्मीर में की जा चुकी हैं।

जम्मू कश्मीर सरकार विकास को गरिमा एवं सामाजिक न्याय के साथ जोड़ती है : उपराज्यपाल सिन्हा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार बनने से लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा बढ़ा है और सहभागी शासन बहाल हुआ है।

सिन्हा ने अपने अभिभाषण के साथ विधानसभा के 27 दिवसीय सत्र की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में विकास को गरिमा, वृद्धि को सामाजिक न्याय और प्रगति को शांति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी से निपटने, बुनियादी ढांचे में खामियों को दूर करने और सामाजिक कल्याण संबंधी उपायों का विस्तार करने पर नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा, ''सरकार ने अपने पहले वर्ष के कार्यकाल में विकास को गरिमा, वृद्धि को सामाजिक न्याय और प्रगति को शांति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।'' सिन्हा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, संविदा कर्मियों और हाशिये पर रहने को मजबूर वर्गों सहित आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है तथा उनसे जुड़े फैसलों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, ''1,500 से अधिक सार्वजनिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं और समय पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए 391 सेवाओं को स्वतः अपील प्रणाली से जोड़ा गया है।''

सिन्हा ने कई वर्षों के अंतराल के बाद निर्वाचित सरकार के गठन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि जन-निर्वाचित सरकार आने से लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है और सहभागी शासन बहाल हुआ है। उन्होंने कहा, ''सरकार स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल शासन के गहन एकीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है।''

एअर इंडिया के पायलट ने ड्रीमलाइनर के ईंधन नियंत्रण स्विच में संभावित खराबी की सूचना दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। एअर इंडिया के एक पायलट ने सोमवार को बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के ईंधन नियंत्रण 'स्विच' में संभावित खराबी की सूचना दी तथा इसकी जानकारी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार, लंदन से बेंगलूरु आ रहा विमान (उड़ान संख्या एआई132) सोमवार सुबह बेंगलूरु में उतरा।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि वह इस बात से अवगत है कि उसके एक पायलट ने बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच में संभावित खराबी की सूचना दी। बयान में कहा गया, ''यह प्रारंभिक जानकारी मिलने के बाद, हमने उक्त विमान को उड़ान भरने से रोक दिया है और पायलट की चिंताओं की प्राथमिकता के आधार पर जांच कराने के लिए निर्माता कंपनी से संपर्क कर रहे हैं।'' इसमें कहा गया, ''मामले की जानकारी डीजीसीए को दे दी गई है और एअर इंडिया ने डीजीसीए के निर्देश पर अपने बेड़े के सभी बोइंग 787 विमानों के ईंधन नियंत्रण 'स्विच' की जांच की। हालांकि उसमें कोई समस्या नहीं पाई गई।'' यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल जून में हुई एअर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना के बाद से ही इसके ईंधन नियंत्रण 'स्विच' की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। देश के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक दुर्घटना 12 जून 2025 को हुई थी जब अहमदाबाद से लंदन जा रहा एअर इंडिया का विमान (एआई171) उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी।

टीवीके बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, केवल हम द्रमुक को हरा सकते हैं : विजय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। अभिनय जगत से राजनीति में कदम रखने वाले विजय ने सोमवार को कहा कि जनता के अपार समर्थन के कारण तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को केवल उनकी पार्टी ही अपने दम पर हरा सकती है।

विजय ने कहा कि हालांकि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन चुनावी लड़ाई केवल टीवीके और द्रमुक के बीच होगी और अंतत: चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की हार होगी। विजय ने टीवीके के स्थापना के तीन साल होने के अवसर पर कहा, ''लोग त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं। एक तरफ जनता समर्थित टीवीके है, दूसरी तरफ द्रमुक और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा उसके कई सहयोगी दल हैं।

हालांकि, टीवीके, जो जनशक्ति के रूप में उभरी है और वह अकेले द्रमुक को हरा सकती है।'' टीवीके की स्थापना के अवसर पर सदस्यों को संबोधित करते हुए पार्टी संस्थापक विजय ने कहा, ''आज हम आपके और जनता के प्रयासों से एक बड़ी पार्टी बन पाए हैं। आप ही मेरी ताकत हैं। मैं और हमारी पार्टी आप पर निर्भर हैं।'' उन्होंने दावा किया कि केवल उनकी टीवीके पार्टी में ही द्रमुक का विरोध करने का साहस है। विजय ने राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक को 'प्लैटिनम जुबली बेबी' करार दिया।

द्रमुक इस समय अपनी स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रही है। विजय ने दावा किया कि वह इस साल 'ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम' (अन्नाद्रमुक)के दिग्गज नेता एम जी रामचंद्रन की सफलता की कहानी को दोहराएंगे।

उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों के पास टीवीके के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधने को लेकर द्रमुक ने विजय का मजाक उड़ाया

चेन्नई/भाषा। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने सोमवार को टीवीके संस्थापक विजय के उस बयान का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नींद में भी लोगों से उनकी पार्टी को वोट देने के लिए कहेंगे।

द्रमुक प्रवक्ता टीकेएस इलैंगोवन ने कटाक्ष करते हुए कहा अभिनेता-राजनीतिक नेता ने राज्य के विकास में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा, ''विजय की वजह से तमिलनाडु जीडीपी में नंबर एक पर है। और हर कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और जब वह चैन से सो रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री लोगों से उनके लिए वोट देने को कहेंगे।'' उन्होंने कहा, ''क्या गजब का दिमाग है उनका।'' द्रमुक के संगठन सचिव ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि वह (विजय) मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए मौजूदा मुख्यमंत्री (स्टालिन) की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने आज की गई विजय की टिप्पणी का जवाब देते हुए यह बात कही। विजय ने दावा किया था कि जब स्टालिन से गहरी नींद में भी पूछा जाएगा, तो वह लोगों से 'सीटी' (टीवीके के चुनाव चिह्न) को वोट देने के लिए कहेंगे। टीवीके संस्थापक ने यह भी दावा किया कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी लड़ाई केवल टीवीके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली ''शुद्ध शक्ति'' और द्रमुक द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली ''बुरी शक्ति'' के बीच है। विजय की इस टिप्पणी पर कि हर घर से ''विजय और विजी'' बड़ी संख्या में मतदान के दिन बाहर निकलेंगे और टीवीके को वोट देंगे, द्रमुक प्रवक्ता ने कहा, ''यह उनका सपना है।''

राजग सरकार की विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला 'कर्तव्य' बजट : भाजपा नेता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय सह-प्रभारी पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट एक ''कर्तव्य'' बजट है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पूर्व विधान परिषद सदस्य ने सात उच्च गति रेल गलियारे (मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलूरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलूरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी) विकसित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया और इन्हें ''पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए जोड़ने वाली सुविधा'' बताते हुए कहा कि इनसे क्षेत्रीय संपर्क, आवागमन और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

रेड्डी ने इसे समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास की दिशा में 'कर्तव्य' और दूरदर्शी बजट बताते हुए सोमवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि इस बजट ने समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए राजग सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाया और इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को मजबूत करने, युवाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण भारत के उत्थान एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उन्होंने शहर आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) पर दिए गए जोर की विशेष रूप से सराहना की और शहरों को विकास, नवोन्मेष और अवसर का केंद्र बताया। उन्होंने कहा, ''आधुनिक ढांचे और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के जरिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों तथा तीर्थ नगरों पर बजट का ध्यान विकेंद्रीकृत विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है।''

रेड्डी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत समावेशी विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भर भारत की भावना के बल पर विकसित भारत की ओर मजबूती से बढ़ रहा है।

कमल हासन ने दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार जीतने पर दी बधाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। अभिनेता-नेता कमल हासन ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार जीतने पर सोमवार को बधाई दी।

दलाई लामा ने लॉस एंजिलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवॉर्ड में 'ऑडियोबुक नैरेशन' श्रेणी में अपनी एल्बम 'मेडिटेशंस: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' के लिए यह पुरस्कार जीता। उन्होंने इस श्रेणी में कैथी गार्वर (एल्विस रॉकी एंड मी: द कैरल कॉनर्स स्टोरी), ट्रेवर नोआ (इंटू द अनकट ग्रास), केतनजी ब्राउन जैक्सन (लवली वन: ए मेमॉयर) और फैब मोरवन (यू नो इट्स ट्रू: द रियल स्टोरी ऑफ मिली वैनिली) जैसे कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार जीता। इस एल्बम का संगीत सरोद वादक अमजद अली खान ने तैयार किया है। कमल हासन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''दुनिया के एक प्रमुख विचारक को सम्मानित कलाकारों की प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल होते देखकर गर्व हो रहा है।'' उन्होंने कहा, ''शब्द इस दुनिया के संगीत में और अधिक अर्थ जोड़ सकते हैं। ग्रैमी को बधाई। अमजद अली खान साहब को भी बधाई।'' दलाई लामा ने यह पुरस्कार मिलने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, ''मैं इस सम्मान को कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। मैं इसे व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि हमारी साझा वैश्विक जिम्मेदारी की मान्यता के रूप में देखता हूं।'' उन्होंने कहा, ''मेरा दृढ़ विश्वास है कि शांति, करुणा, पर्यावरण की देखभाल और मानवता की एकता की समझ, सभी आठ अरब लोगों के सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक है।'' दलाई लामा ने कहा, ''मैं आभारी हूं कि यह ग्रैमी सम्मान इन संदेशों को व्यापक रूप से फैलाने में मदद कर सकता है।''

सरकार ने तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश की लेकिन राज्य इसे स्वीकार नही करेगा : शिवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता टी शिवा ने केंद्र पर तमिलनाडु के साथ भेदभाव करने और राज्य पर हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाया।

शिवा राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने तमिलनाडु में हिंदी व संस्कृत थोपने की कोशिश की लेकिन राज्य इसे नहीं स्वीकार करेगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू नहीं करने पर केंद्र की ओर से आवंटन रोके जाने का दावा करते हुए कहा कि तमिलनाडु में पहले ही राज्य शिक्षा नीति लागू है जिसमें सिर्फ दो ही भाषाएं-तमिल एवं अंग्रेजी का जिक्र है।

शिवा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचा है और यहां तक कि विधेयक भी जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का भी महत्व है लेकिन यह सरकार इसे स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान में राज्यों के अधिकारों का जिक्र है लेकिन यह सरकार विपक्ष शासित राज्यों को उनके हक से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मानकों पर तमिलनाडु देश में पहले नंबर पर है लेकिन उसके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा है।

द्रमुक सदस्य ने कहा कि जो राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए न कि उनका उत्पीड़न किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विभिन्न विकसित शहरों के लिए मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा रही है।

शिवा ने देश में धन के असमान वितरण को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार कुछ उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'डबल इंजन' सरकार की बात करते हैं यानी केंद्र एवं राज्य में एक ही दल की सरकार। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 'डबल इंजन' सरकार ही थी लेकिन वहां क्या हुआ, सब जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि गणतंत्र दिवस के दिन उत्तर प्रदेश में एक मंत्री ने आपत्तिजनक आचरण किया।

राज्यसभा में अन्नाद्रमुक सदस्य ने की जयललिता को भारत रत्न दिए जाने की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में सोमवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के एक सदस्य ने अपनी पार्टी की दिवंगत प्रमुख एवं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' दिए जाने की मांग की।

शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए अन्नाद्रमुक के एम धनपाल ने कहा कि जयललिता ने अपना पूरा जीवन गरीबों, वंचिता और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अपनी दूरदर्शी सोच से जयललिता ने तमिलनाडु में जनकल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू कीं और उनका आम जनता को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए जयललिता ने अथक परिश्रम किया तथा राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की मांग की।

'आम' चुनाव चिह्न संबंधी रामदास की याचिका पर अदालत का निर्वाचन आयोग को नोटिस

चेन्नई/भाषा। मद्रास उच्च न्यायालय ने पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक अध्यक्ष एस. रामदास की उस याचिका पर निर्वाचन आयोग को सोमवार को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को 'आम' चुनाव चिह्न आवंटित करने और इस संबंध में उन्हें आधिकारिक सूचना भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने पीएमके की याचिका की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी। जब यह याचिका सुनवाई के लिए खंडपीठ के समक्ष आई, तो रामदास की ओर से पेश अधिवक्ता के. अरुल ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अनजाने में पूर्व अध्यक्ष अंबुमणि के पते पर 'आम' चुनाव चिह्न आवंटित करने वाला एक पत्र भेज दिया, जो अब पार्टी के सदस्य भी नहीं हैं। जब अंबुमणि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन.एल. राजा ने अपनी दलील पेश करने का प्रयास किया, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप मुकदमे में पक्षकार है ही नहीं। राजा ने कहा कि वह इस मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दाखिल करेंगे।

अपनी याचिका में रामदास ने आरोप लगाया कि अंबुमणि ने जाली दस्तावेज बनाकर निर्वाचन आयोग के साथ धोखाधड़ी की है। इन जाली दस्तावेजों को चार दिसंबर, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अध्यक्ष रामदास के नेतृत्व में पदाधिकारियों के नामों में परिवर्तन और उनके कार्यालय के पते में बदलाव की सूचना भी निर्वाचन आयोग को दे दी गई थी। आयोग से 'आम' चुनाव चिह्न आवंटित करने का भी अनुरोध किया गया था। इस स्थिति के बावजूद, आयोग ने पिछले एक महीने में कोई जवाब नहीं दिया। जब मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आया, तो आयोग के वकील ने खुली अदालत में बहस करते कहा, चूंकि दो गुटों के पुत्र और पिता के बीच पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर विवाद है, इसलिए निर्वाचन आयोग 2026 के चुनावों के लिए 'आम' चुनाव चिह्न को निलंबित रखेगा।

बेपोर से यूडीएफ उम्मीदवार होंगे पी.वी. अनवर: सनी जोसेफ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोझिकोड/भाषा। केरल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने भले ही अभी अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा नहीं की है लेकिन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने सोमवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता पी.वी. अनवर कोझिकोड जिले के बेपोर विधानसभा क्षेत्र से यूडीएफ के उम्मीदवार होंगे।

वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के पूर्व विधायक अनवर ने वाम मोर्चा छोड़ने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसे हाल में यूडीएफ का सहयोगी दल बनाया गया है। आगामी विधानसभा चुनावों में रियास के खिलाफ अनवर के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच तृणमूल नेता पिछले कई हफ्तों से बेपोर निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय हैं। रियास मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के दामाद भी हैं। अनवर की उम्मीदवारी को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में जोसेफ ने पुष्टि की कि तृणमूल नेता यूडीएफ के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा, वह जरूर जीत हासिल करेंगे और बेपोर के विधायक बनेंगे। हालांकि, इसके बाद जोसेफ ने इस विषय पर और कुछ नहीं कहा। सोमवार को अनवर ने चलियम बंदरगाह का दौरा किया और मछुआरों तथा मछली व्यापारियों से बातचीत की।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी उम्मीदवारी तय है, तो अनवर ने स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''किसी को तो चुनाव लड़ना ही है। फैसला बाद में होगा। देखते हैं।'' रियास को लेकर की गई अपनी टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, अनवर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पर्यटन मंत्री रियास एक नेता हैं। अनवर अक्सर रियास के लिए ''दामाद'' शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ''लेकिन सरकार और माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) एक ही परिवार की मुट्ठी में है। यहां (कोझिकोड) से माकपा के वे बड़े नेता कहां हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया? अब तो कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं हैं।'' अनवर ने यह भी आरोप लगाया कि रियास आम लोगों से जुड़े मुद्दों को हल करने में नाकाम रहे हैं।

यूडीएफ के चुनाव प्रचार को लेकर लोगों में भारी उत्साह होने का दावा करते हुए अनवर ने एलडीएफ की राज्यव्यापी विकास रैली की आलोचना की। उन्होंने कहा, ''एलडीएफ पूरे राज्य में विकास रैली कर रही है। अगर वास्तव में विकास हुआ है तो ऐसी रैली की क्या जरूरत है? यह एक छलावा है।'' माकपा और एलडीएफ ने अनवर के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

अनवर ने इससे पहले मलप्पुरम जिले के नीलांबुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था। अब उन्होंने अपना ध्यान बेपोर पर केंद्रित कर लिया है, क्योंकि यूडीएफ आने वाले हफ्तों में उम्मीदवारों की घोषणा और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे सकता है।

कांग्रेस ने एलडीएफ के खिलाफ 'कड़कु पूड़थ' डिजिटल अभियान शुरू किया

तिरुवंनतपुरम/भाषा। केरल में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार को 'कड़कु पूड़थ' (यहां से चले जाओ) नाम से एक राज्यव्यापी डिजिटल अभियान शुरू किया। इस अभियान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ)को सीधा निशाना बनाया गया है। कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा यह नारा विजयन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 2017 में पत्रकारों को इसी वाक्यांश का इस्तेमाल करते हुए बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम से चले जाने को कहा था। पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष इस टिप्पणी का इस्तेमाल उनके सत्तावादी शासन शैली के प्रतीक के रूप में कर रहा है। विपक्ष इस वाक्यांश के सहारे उनकी शासन शैली का वर्णन करता है।

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) मुख्यमंत्री के अपने ही शब्दों 'कड़कु पूड़थ' को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है, और इस अभियान को सत्ता से उन्हें हटाए जाने की सार्वजनिक मांग के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इस अभियान के केंद्र में हाल ही में शुरू की गई एक वेबसाइट है, जहां नागरिक एलडीएफ सरकार के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस वेबसाइट का प्रचार मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा रहा है, जो संदेश के प्रतीकात्मक महत्व को रेखांकित करता है। कांग्रेस ने भी एलडीएफ सरकार पर व्यापक कुशासन का आरोप लगाते हुए एक विस्तृत आरोपपत्र जारी किया है। इन आरोपों में बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक संकट, कृषि संकट, मादक पदार्थों का बढ़ता इस्तेमाल, वन्यजीवों पर बढ़ते हमले और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का 'लगातार क्षरण' शामिल हैं। कांग्रेस कथित भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री द्वारा पूरे न किए गए वादे और शबरिमला से सोने की चोरी सहित मंदिरों से चोरी जैसे मुद्दे भी उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डिजिटल अभियान का उद्देश्य जनता के बढ़ते आक्रोश को सही दिशा देना और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है, खासकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच।

केरल में कैदियों को पैरोल

स्थगन प्रस्ताव खारिज किए जाने को लेकर विपक्ष का कार्यवाही का बहिष्कार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल विधानसभा में विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के विधायकों ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए माकपा कार्यकर्ताओं को पैरोल देने का एलडीएफ सरकार पर आरोप लगाते हुए सोमवार को सदन में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा खारिज किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया।

विधानसभा सत्र की शुरुआत ही विपक्षी नेताओं के बहिर्गमन से हुई। उन्होंने शबरिमला स्वर्ण चोरी मामले को लेकर देवस्वओम मंत्री वी. एन. वासवन के इस्तीफे की मांग की।

प्रश्नकाल के बाद रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (आरएमपीआई) की विधायक के. के. रेमा ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में सजा पाए दोषियों समेत कई कैदियों को पैरोल दी गई और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

हालांकि, अध्यक्ष ए. एम. शमसीर ने प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसपर तत्काल विचार किया जाए और इसे बाद में भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है।

नेता प्रतिपक्ष वी. डी. सतीशन ने नोटिस खारिज किए जाने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अपराधियों को अवैध रूप से पैरोल दी जा रही है, जिससे बाहर कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो रही हैं।

सतीशन ने कहा कि माकपा नेता और पय्यानूर नगर पार्षद वी. के. निषाद को पिछले साल दिसंबर में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और उसे एक महीने बाद ही पैरोल दे दी गई।

संसदीय कार्य मंत्री एम बी राजेश ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि निषाद को आठ जनवरी को पैरोल दी गई थी, लेकिन पिछले महीने विधानसभा सत्र शुरू होने पर यह मुद्दा नहीं उठाया गया था। उन्होंने कहा, ''विपक्ष के पास विधानसभा में उठाने के लिए विषयों की कमी है और इसी कारण ऐसा प्रस्ताव लाया गया है।''

बाद में विपक्षी विधायकों ने हाथों में तख्तियां उठा लीं। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इन सदस्यों को पता था कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए वे मुद्रित सामग्री सदन में लाए थे।

शमसीर ने कहा, ''वे लोग नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा हो।''

इसके बाद विपक्षी विधायक सदन में आसन के पास पहुंच गए और दोषी कैदियों को पैरोल दिए जाने के विरोध में बैनर लहराते हुए नारे लगाने लगे।

इसके बाद, विपक्षी विधायकों ने एक बैनर लहराते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

हालांकि, विरोध प्रदर्शन के बावजूद सदन की कार्यवाही जारी रही, जिसमें एलडीएफ के विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य विधायी कार्यों में शामिल हुए।

नए बजटीय प्रावधानों और इंसेंटिव्स का लाभ लेने के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल से देश वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने रविवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को आत्मनिर्भर से विकसित, संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की प्रतिबद्धता का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट पर सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति केन्द्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने वाले प्रावधान किए गए हैं, इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, 1 लाख 50 हजार केयर गिवर्स और टूरिस्ट गाइड्स को कौशल प्रशिक्षण से भी युवाओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एवीजीसीएक्सआर पॉलिसी पहले ही लागू की जा चुकी है। अब माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेट क्रियेटर लैब्स की स्थापना से राजस्थान के युवाओं को दोहरा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने, कृषि अवसंरचना एवं बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने और जोखिम घटाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

शर्मा ने कहा यूरोप के साथ ऐतिहासिक समझौता होने के बाद इस बजट ने देश के छोटे-बड़े उद्योगों, मैन्युफैक्चरर्स, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जगह बनाने के लिए नई दिशा दिखाई है। बायो फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। उन्होंने उद्योग जगत का आह्वान किया कि कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की हैवी मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट में लाई गई विशेष योजना का लाभ लेते हुए राजस्थान के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अपनी इकाइयां लगाएं। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश के निर्यातकों को नए खुल रहे बाजारों में निर्यात वृद्धि के अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में राजस्थान की संभावनाओं और आवश्यकताओं को पूरा स्थान मिला है। अक्षय ऊर्जा के लिए 30 प्रतिशत ज्यादा करीब 32 हजार 914 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार पीएम सूर्यघर योजना को 22 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। सोलर ग्लास मैन्युफेक्चरिंग में प्रयोग आने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। बीईएसएस में उपयोग में आने वाले लीथियम आयन सेल बैटरी निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। राजस्थान सौर ऊर्जा में पहले से ही अग्रणी प्रदेश है, अब इन प्रावधानों से प्रदेश के सौर ऊर्जा क्षेत्र को नई गति मिलेगी।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति, एआईएमएल नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की हैं। इसलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट मेनुफेक्चरिंग स्कीम, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को दिए गए इंसेंटिव्स का फायदा लेते हुए सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत टॉपअप छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात हैं।

महात्मा गांधी स्वराज योजना और चैम्पियन एमएसएमई बनाने की पहल से राजस्थान के छोटे उद्योगों के ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने की राह प्रशस्त होगी। मेगा टैक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और देशभर में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से मजबूत करने की घोषणा भी राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में अवसंरचना विकास पर विशेष जोर देते हुए 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के शहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए अधिक राशि मिल सकेगी। इनविट बॉन्डस, आरईआईटी और म्युनिसिपल बॉन्डस से मिलने वाले आर्थिक संबल से प्रदेश के शहर बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने जा रहे हैं।

मादक पदार्थ बनाने वाली इकाई का भंडाफोड़, पांच करोड़ रुपये की एमडी और रसायन जब्त

जयपुर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत शहर के बीचों-बीच एक किराना दुकान और अनाज गोदाम की आड़ में सक्रिय मादक पदार्थ बनाने की इकाई का भंडाफोड़ करते हुए करीब पांच करोड़ रुपये की एमडी और कच्चा माल जब्त किया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक बी.आदित्य ने बताया कि प्रतापगढ़ थाना प्रभारी शंभुसिंह को सूचना मिली थी कि वाटरवर्क्स रोड स्थित नाकोड़ा किराना के पीछे कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम ने गोदाम के अंदर बने गुप्त कमरे की तलाशी ली, जहां से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और उसे बनाने के उपकरण मिले।

अधिकारी ने बताया कि मौके से 106 ग्राम एमडी और एमडी तैयार करने में प्रयुक्त होने वाला 114.750 किलोग्राम तरल रसायन बरामद किया गया।

उन्होंने बताया कि बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब पांच करोड़ रुपये आंकी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मादक पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी धर्मचन्द मोगरा जैन और रोहित मोगरा जैन किराना व्यापार की आड़ में इस कारोबार को अंजाम दे रहे थे तथा पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे मौके से फरार हो गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनी लोगों की शिकायतें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई की और अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने व समाधान में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी गुणवत्तापूर्ण राहत पहुंचाई जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और नीयत के केंद्र में लोककल्याण है। शर्मा ने स्पष्ट किया कि जनसेवा की भावना के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी आमजन की परिवेदनाओं को सुना और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन भी किया।

वीबी-जीरामजी संविधान की आत्मा के खिलाफ : अरुणा रॉय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) को संविधान की आत्मा के खिलाफ बताते हुए सोमवार को कहा कि नया कानून ''रोजगार के अधिकार को केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर बना देता है।'' रॉय यहां शहीद स्मारक पर कांग्रेस और विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल हुईं। इस दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की बहाली और वीबी-जीरामजी को रद्द करने की मांग को लेकर गीत गाकर और नृत्य कर विरोध जताया गया। धरने में अरुणा रॉय के अलावा निखिल डे, कांग्रेस की जयपुर शहर इकाई के अध्यक्ष सुनील शर्मा, गोपाल शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा, चाकसू से पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

इस मौके पर आयोजित मजदूर महापंचायत में अरुणा रॉय ने कहा, वीबी-जीरामजी संविधान की आत्मा के खिलाफ है। मनरेगा ने पहली बार गांव के गरीब को राज्य से काम मांगने का अधिकार दिया था, लेकिन नया कानून उस अधिकार को छीनकर रोजगार को केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर बना देता है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है और केंद्रीकृत नियंत्रण को बढ़ावा देता है।

निखिल डे ने कहा, यह कानून रोजगार की गारंटी नहीं, बल्कि मजदूरों की असुरक्षा की गारंटी है। काम, मजदूरी और योजनातीनों को ग्राम सभा और राज्यों से छीनकर केंद्र सरकार के नियंत्रण में सौंप दिया गया है। अब काम मांगना मजदूर का कानूनी अधिकार नहीं रहा, बल्कि रोजगार कब, कितना और किसे मिलेगा, यह केंद्र सरकार तय करेगी। संसद के बीते शीतकालीन सत्र में मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत-जीरामजी विधेयक' पारित किया गया था, जो अब कानून बन चुका है।

चंबल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन

कोटा। चंबल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नौवां संस्करण रविवार को यहां संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। तीन दिवसीय इस महोत्सव में दुनिया भर की फिल्में प्रदर्शित की गईं और इसका समापन पुरस्कार समारोह के साथ हुआ। इसमें फिल्म 'बैंडिट क्वीन' में अपनी भूमिका के लिए जानी जाने वाली सीमा बिस्वास ने शिरकत की। बिस्वास को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

समापन समारोह के दौरान, बिस्वास ने कोटा की फिल्म पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ती क्षमता की प्रशंसा की और शहर के सिनेमाई आकर्षण को उजागर करने के लिए महोत्सव को श्रेय दिया। 'हम लोग' में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले अभिनेता अभिनव चतुर्वेदी भी इस आयोजन में शामिल हुए। महोत्सव निदेशक डॉ. कपिल सिद्धार्थ ने बताया कि महोत्सव में 101 देशों से प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शित फिल्मों में फीचर फिल्म, वृत्तचित्रों में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषय शामिल थे।

राजस्थान की सामाजिक-आर्थिक यात्रा समावेशी विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। नेशनल डिफेन्स कॉलेज- एनडीसी के प्रतिनिधिमंडल के राजस्थान भ्रमण के अंतर्गत सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों के साथ एक परिचयात्मक एवं संवादात्मक बैठक आयोजित की गई। यह संवाद अंडरस्टैंडिंग इंडिया स्टडी टूर के तहत आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की। इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना व भारतीय राजस्व सेवा के आला अधिकारी तथा विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि शामिल थे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के संवाद से राज्य के प्रशासनिक अनुभव, विकास मॉडल और नीतिगत दृष्टिकोण को साझा करने का सशक्त मंच मिलता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अध्ययन भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल के साथ निरंतर संवाद एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास, प्रशासनिक ढांचे, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रों में संचालित प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समग्र जानकारी प्रदान की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग शिखर अग्रवाल ने औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन नीतियों, औद्योगिक पार्कों, निर्यात संवर्धन एवं रोजगार सृजन से संबंधित पहलुओं की जानकारी साझा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल एवं उद्यमिता, रोजगार विभाग संदीप वर्मा ने कौशल प्रशिक्षण, रोजगार मेलों, अप्रेंटिसशिप, आईटीआई सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के लिए संचालित योजनाओं पर प्रस्तुति दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कुलदीप रांका ने उच्च शिक्षा संस्थानों, छात्रवृत्तियों, बालिका शिक्षा, अधोसंरचना विकास एवं रोजगारोन्मुख पहलों पर जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी, सोलर दीदी एवं ड्रोन दीदी जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह भास्कर आत्माराम सावंत ने आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध नियंत्रण, टास्क फोर्स गठन, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था तथा नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की जानकारी साझा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उर्जा विभाग अजिताभ शर्मा द्वारा समग्र विद्युत क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं, पीएम-कुसुम एवं पीएम-सूर्य घर योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया।

एमएसएमई, मेक इन इंडिया और सनराइज सेक्टर्स को नई रफ्तार देगा केन्द्रीय बजट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष (राज्य मंत्री) प्रहलाद राय टांक ने सोमवार को राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुँच कर केन्द्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2026-27 में देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। यह बजट मात्र औपचारिक एवं लोक लुभावना न होकर धरातल पर ठोस बदलाव लाने वाला है जो वर्ष 2047 तक ''विकसित भारत'' बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है।

टांक ने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है, और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, महंगाई कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही, बजट में हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। आज भारत के 140 करोड़ नागरिक, केवल सबसे तेजी से बढ़ती इकोनोमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं।

आज भारत दुनिया में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने कई बड़ी-बड़ी ट्रेड डील्स की हैं। इसी तरह का एक उदाहरण युरोपियन यूनियन के साथ हुई मदर ऑफ ऑल डील्स है। इन समझौतों का अधिकतम लाभ देश के युवाओं और हमारे लघु व मध्यम उद्योगों को मिले इसी सोच के साथ केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण और बड़े कदम उठाए गए हैं।

टांक ने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ़्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज़, यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वो अभूतपूर्व है। इस बजट के प्रमुख प्रावधानों में बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिक्ल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाई टेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमई तैयार करना है।

राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान

जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में कई जगह बारिश हुई है और मौसम विभाग के अनुसार अभी यह दौर जारी रहेगा और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम केंद्र (जयपुर) के अनुसार सोमवार सुबह तक के 24 घंटों में राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में हुई, जो 13 मिलीमीटर दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश आगामी दो से तीन दिन जारी रहने व शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने का अनुमान है।

विकास, गरीब-किसान और रोजगार को समर्पित है केंद्रीय बजट : रावत

जयपुर। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सोमवार को मीडियाकर्मियों के साथ सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बजट की समग्र विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास, आर्थिक मजबूती और आमजन के हितों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट में गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा गया है। बजट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण-शहरी विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधान देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

उन्होंने कहा कि यह बजट राज्यों के साथ समन्वय को मजबूत करेगा और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही बजट में वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को प्राथमिकता दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार का यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को साकार करता है।

उन्होंने टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में बजट को लेकर होने वाले विशेष लाभ व ईआरसीपी परियोजना, माही व जाखम नदी से मेजा बांध में पानी लाने की संभावनाओं सहित अन्य विषयों पर विचार व्यक्त किये साथ ही मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उन्होंने सहजता से जवाब दिए।

गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने वाला दूरदर्शी बजट : किरोड़ी लाल मीणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रदेश के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को सवाई माधोपुर जिला कलक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय बजट 2026 के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, मध्यम वर्ग और उद्यमी के लिए स्पष्ट दिशा एवं मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाला बजट है।

डॉ. मीणा ने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत की 'ग्रोथ इंजन' हैं। महिला शिक्षा और सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी 41 जिलों में महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। बजट में भारत स्किल इंडिया, डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में आई.आई.एम. के सहयोग से 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से अगले दशक में खेल क्षेत्र में बदलाव लाने की योजना से युवाओं को नई दिशा मिलेगी।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा : मुख्यमंत्री योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर से तेजी से आगे बढ़ा है।

केंद्रीय बजट की विशेषताओं को लेकर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ''दूरदर्शी'' बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से तैयार होकर सामने आया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह बजट हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का बोध कराता है और इसमें भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश की 25 करोड़ से अधिक आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकलकर भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने कहा, ''इसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है।''

मुख्यमंत्री ने कहा, ''2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था और उनका निरंतर आग्रह रहा है कि हमें 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने मौलिक

अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों पर भी राष्ट्रव्यापी चर्चा का आह्वान किया था।'' योगी ने कहा, ''हम मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों पर चर्चा नहीं करते। राष्ट्र और समाज के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों को समझना और निभाना आवश्यक है।'' उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, महिलाएं, गरीब और वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर तथा पूरे देश में समान और समावेशी विकास के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने वर्ष 2026-27 का बजट संसद में प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए गए प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी नीतियां और योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका स्पष्ट प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि जब नीतियां स्पष्ट हों व संकल्प दृढ़ हो, तो परिणाम भी स्पष्ट होते हैं और वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की तेज प्रगति इसी स्पष्टता तथा दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती है। योगी ने कहा कि यह बजट सुधार, विकास और राजकोषीय अनुशासन का संतुलित दस्तावेज है, जो नए भारत के निर्माण के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आम बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश को 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि बजट का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाला पहलू एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में देश का नेतृत्व करता है और प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई आधार है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, योगी ने कहा कि 'ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश के भीतर देश का सबसे बड़ा 'लॉजिस्टिक्स हब' विकसित हो रहा है और इसका सीधा लाभ उद्योग, व्यापार व रोजगार सृजन के रूप में उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा।

बेतुकी दलीलों का प्रचार करने वाले राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं : नकवी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रामपुर (उप्र)/भाषा। केंद्रीय बजट की आलोचना करने को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि कुछ लोग अब 'बेतुकी दलीलों का प्रचार करने वाले बनकर रह गए' हैं और दावा किया कि हंगामा करने वाले ये तत्व राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।

नकवी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 'आत्मनिर्भर भारत की गूंज और विकसित भारत की गर्जना का गजट है और विकसित भारत की अभूतपूर्व क्षमता को साकार करने के संकल्प का एक मजबूत दस्तावेज है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, वैश्विक कठिनाइयों और मंदी के बीच भी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन की ताकत ने बाहरी उथल-पुथल और आंतरिक बाधाओं को पार करते हुए विश्वसनीयता और स्थिरता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत और सफल यात्रा को लगातार बनाए रखा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों द्वारा बजट की आलोचना पर, नकवी ने कहा कि कुछ लोग अपने 'बौद्धिक दिवालियापन के कारण बेतुकी दलीलों का प्रचार करने वाले बनकर रह गए हैं'।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसलिए, हंगामा करने वाले ये तत्व राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया, भाजपा ने दशकों से चली आ रही राजनीतिक असहिष्णुता और अस्पृश्यता पर विजय प्राप्त कर ली है और सुशासन, स्थिरता और समावेशी सशक्तीकरण के वैश्विक ब्रांड के रूप में उभरी है।

नकवी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कुछ राजनीतिक दल पराजित लोगों की प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन की ताकत को विपक्ष के अहंकार और अराजकता से नहीं तोड़ा जा सकता।

बजट 2026-27: झारखंड के रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 7,536 करोड़ रुपए आवंटित

रांची/भाषा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में झारखंड में रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए 7,536 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस राज्य में 63,470 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का काम जारी है। वैष्णव ने कहा, ''झारखंड को 12 से अधिक वंदे भारत और चार अमृत भारत ट्रेन आवंटित की गई हैं। राज्य में दो और अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना पर काम जारी है। प्रस्तावित दो अमृत भारत ट्रेन में से एक को धनबाद-कोयंबटूर मार्ग के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा। झारखंड में संपर्क परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थीं। मंत्री ने कहा, ''उन सभी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है तथा मंजूरी लेने की प्रक्रिया जारी है।''

बिहार: व्हीलचेयर पर बैठ विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव

पटना/भाषा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को व्हीलचेयर पर बिहार विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बताया कि पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है। राज्यपाल द्वारा बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को संबोधित किए जाने के बाद 36 वर्षीय नेता प्रतिपक्ष पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे बाएं पैर के बड़े अंगूठे में हाल ही में चोट लग गई थी। नाखून को शल्य चिकित्सा के जरिए हटाना पड़ा। इसके कारण चलना मुश्किल हो गया है। तेजस्वी यादव को हाल ही में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया गया था और इसमें विकास की गुलाबी तस्वीर पेश की गई, जबकि विकास के अधिकांश सूचकों में बिहार कई अन्य राज्यों से पीछे है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, सरकार इस बात पर चुप है कि ऐसा क्यों है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से सत्ता में हैं। इसके अलावा दुष्कर्म, हत्याएं व अन्य अपराध लगातार हो रहे हैं और सरकार का कानून-व्यवस्था का दावा खोखला साबित हो रहा है।

भारत में फार्मूला वन फिर शुरू करना चाहता है खेल मंत्रालय

नई दिल्ली/भाषा। खेल मंत्रालय भविष्य में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर फार्मूला वन फिर शुरू करने का इच्छुक है और 2013 में आखिरी बार भारत में हुई रेस फिर शुरू करने के लिए ट्रैक अधिकारियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि खेलमंत्री मनसुख मांडविया पिछले सप्ताह ग्रेटर नोएडा में ट्रैक का दौरा कर चुके हैं । उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बात भी की है जिसने अब दिवालिया को चुके ट्रैक के मालिक जेपी समूह से परिसर अपने नियंत्रण में ले लिया है । अडानी समूह जेपी समूह खरीदने की दौड़ में है और अगर ऐसा हो गया तो भारत में रेस को वापिस लाने की कोशिशों को बल मिलेगा । अब खेल मंत्रालय ने भी इसमें रूचि दिखाई है तो संभावनायें बढ गई है ।

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को बताया ''ग्रेड डी'' सरकार

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह ''ग्रेड डी'' सरकार है जो जमीनी वास्तविकताओं से दूर है और लोगों से किए गए उसके विभिन्न वादे भी अधूरे हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सदस्य सागरिका घोष ने दावा किया कि सरकार जमीनी चुनौतियों से दूर है और अपनी असफलता को लेकर आत्मचिंतन भी नहीं करती। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को मतदान का अधिकार है लेकिन मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों से मतदान करने का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि नामों में मामूली विसंगति होने पर भी आपत्ति जतायी जा रही है और अमर्त्य सेन सहित कई मशहूर लोगों को एसआईआर के नाम पर समन किया गया। तृणमूल सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र की बात की गई है लेकिन सचाई कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि जीएसटी सहित कई क्षेत्रों में भारी अनियमितताएं हैं।

पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने के लिए 40 किमी भूमिगत रेल गलियारे की योजना : वैष्णव

गुवाहाटी/भाषा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि पूर्वोत्तर भारत को देश की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले रणनीतिक रूप से अहम 40 किलोमीटर लंबे सिलीगुड़ी गलियारे में भूमिगत रेल पटरी बिछाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से होकर गुजरने वाला संकरा भू-गलियारा, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत के अन्य भागों से जोड़ता है, अक्सर 'चिकेन नेक' के नाम से जाना जाता है।

अश्विनी वैष्णव ने आम बजट में रेल मंत्रालय संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आयोजित ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले 40 किलोमीटर लंबे रणनीतिक गलियारे के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। भूमिगत रेलवे ट्रैक बिछाने और मौजूदा ट्रैक को चार लेन का बनाने की योजना पर काम हो रहा है।''

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने योजना के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि भूमिगत रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल में टिन मिले हाट और रंगापानी रेलवे स्टेशनों के बीच होंगी। उन्होंने कहा, ''सुरक्षा की दृष्टि से यह भूमिगत मार्ग महत्वपूर्ण है।''

केंद्रीय बजट: ओडिशा में रेलवे क्षेत्र के विकास के लिए 10,928 करोड़ रुपए आवंटित किए गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में ओडिशा में रेलवे क्षेत्र के विकास के लिए 10,928 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि राज्य में 90,659 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा, हमने ओडिशा में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का वादा किया था। अब, हाल ही में हुए बजट आवंटन के साथ, रेलवे क्षेत्र में कुल निवेश जल्द ही एक लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आवंटन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 2009 से 2014 के कार्यकाल के दौरान ओडिशा को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवंटित औसत राशि 838 करोड़ रुपए से 13 गुना अधिक है। राज्य को वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 10,599 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। रेल मंत्री ने कहा कि पूर्व-पश्चिम माल ढुलाई गलियारा परियोजना से ओडिशा को भी लाभ होगा। 2,052 किलोमीटर लंबा यह गलियारा पश्चिम बंगाल के डंकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ेगा। उन्होंने कहा, ''यह गलियारा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरेगा। यह गलियारा ओडिशा में औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

नरवणे के संस्मरण को लेकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पर राहुल का निशाना

सरकार का गुमराह करने का आरोप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण के मसौदे के कुछ अंश का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि किताब की बातें सामने आईं तो देश को भाजपा के दोनों प्रमुख नेताओं की असलियत पता चल जाएगी और यह भी मालूम पड जाएगा कि चीन के सामने '56 इंच की छाती' का क्या हुआ।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वह ''काल्पनिक बातें'' करके सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और सेना पर सवाल उठा रहे हैं।

राहुल गांधी की ओर से कई बार यह मुद्दा उठाए जाने की कोशिश करने पर सदन में सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला तथा कार्यवाही बाधित हुई।

लोकसभा में गतिरोध बने रहने पर सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद शाम चार बजकर 10 मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बोलने नहीं दिया जा रहा है और सरकार इस बात से डरी हुई है कि यदि पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की पुस्तक की बातें सामने आ जाएंगी तो ''प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री सिंह की असलियत देश को पता चल जाएगी।'' राहुल गांधी का यह भी कहना था कि देश को यह भी पता चलेगा कि जब चीन के सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो ''56 इंच की छाती'' का क्या हुआ था। उन्होंने दावा किया, ''नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह और पूरी सरकार सिर्फ एक लाइन से डरी हुई है। वो लाइन मैं संसद में बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।'' बाद में राहुल ने 'एक्स' पर लिखा, ''पूर्व सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि मोदी जी और राजनाथ जी ने सेना को कैसे निराश किया। अपने पर्दाफाश के डर से वे मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे।'' कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के मसौदे के उस अंश को पढ़ना चाहते थे जिसमें 31 अगस्त, 2020 की एक घटना का उल्लेख है। यह संस्मरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए पलटवार करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति और चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वह पूर्व सेना प्रमुख के उस संस्मरण के अंश को पढ़ना चाहते हैं जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने जैसे ही इसे पढ़ने का प्रयास किया तो राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं।

मुख्यमंत्री सोरेन ने आदिवासियों से बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चाईबासा/भाषा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को आदिवासी समुदाय से अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया और कहा कि सरकार उनके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

पश्चिम सिंहभूम के सेरेंगसिया घाटी में आदिवासी जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए 1837 में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहूति देने वाले पोटो हो के नेतृत्व में शहीद हुए आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी के कारण दशकों से आदिवासियों का शोषण किया गया है। उन्होंने समुदाय के बच्चों में शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, हमारी पिछड़ेपन और कमजोरी का कारण निरक्षरता थी।

मुख्यमंत्री ने 'सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना' और 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड' जैसी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब माता-पिता के वित्तीय बोझ को कम करना है, ताकि उनके बच्चे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उन्होंने कहा, सरकार ने गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए एक निःशुल्क आवासीय कोचिंग सेंटर भी शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे समुदाय से एक भी न्यायाधीश क्यों नहीं है, जबकि हमारे कुछ वकील हो सकते हैं? हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, इसलिए हमें ऐसे आदिवासी न्यायाधीशों की आवश्यकता है, जो छोटानागपुर और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियमों को समझें और हमारी जमीनों की रक्षा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हो, चांद भैरव और पोटो हो जैसे आदिवासी शहीदों ने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और झारखंड का निर्माण उसी अनुरूप करना समुदाय की जिम्मेदारी है, जैसा उन लोगों ने कल्पना की थी।

बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना, सबसे गरीब शिवहर: आर्थिक सर्वेक्षण

पटना/भाषा। बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना है जबकि सबसे गरीब जिला शिवहर है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यह जानकारी सामने आई है।

सर्वेक्षण के मुताबिक, अमीरी के मामले में पटना के बाद दूसरे स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर मुंगेर जिला है। वहीं गरीबी के मामले में शिवहर के बाद अररिया दूसरे और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पर है। सर्वेक्षण में बताया गया कि राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपए है, जबकि पटना की प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 रुपए दर्ज की गई है। वहीं बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय 61,566 रुपए और मुंगेर में 54,469 रुपए है। सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्य के सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है।

आईसीसी को पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी चाहिए : गावस्कर, भज्जी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का अनुमान है कि पाकिस्तान 'यू टर्न' लेगा लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ 15 फरवरी को टी20 विश्व कप के मैच का बहिष्कार करने पर आईसीसी को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए । पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि उसकी टीम कोलंबो में भारत के खिलाफ यह मैच नहीं खेलेगी और इसका कोई आधिकारिक कारण भी नहीं दिया । ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यह कदम उठाया गया है । बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर कर दिया गया है जिसने सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार किया था ।

गावस्कर ने 'इंडिया टुडे' से कहा ,'' मुझे लगता है कि अगले चार या पांच दिन में दुनिया भर से प्रतिक्रिया आने लगेगी तो संभव है कि पाकिस्तान अपना फैसला बदल ले ।'' टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होगा और पाकिस्तान को सारे मैच श्रीलंका में खेलने हैं ।

गावस्कर ने कहा ,''इसमें क्या नया है । हम सभी को पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होते हैं और चार दिन बाद फैसला बदलकर कहते हैं कि हमारे प्रशंसकों ने और खेलने के लिए कहा है ।'' उन्होंने कहा ,''पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मिसाल कायम की है । वे संन्यास का फैसला बदलते रहते हैं लिहाजा 15 फरवरी से पहले ऐसा कुछ हो सकता है ।'' गावस्कर और हरभजन सिंह दोनों ने कहा कि अगर आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करती है तो यह सही होगा । उन्होंने कहा ,'' पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ बड़े मैच से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है । अनुबंध का उल्लंघन करने का कारण नहीं बता पाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ।'' हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा ,'' पहले उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन बांग्लादेश के मसले के बाद वे इसमें कूद पड़े । इस फैसले का असर आईसीसी पर पड़ सकता है लिहाजा आईसीसी को कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है । इससे पूरे टूर्नामेंट पर असर पड़ सकता है ।''

हर प्रारूप की भारतीय पुरुष टीम में 'अविश्वसनीय' प्रतिभा का स्तर : सारा टेलर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वडोदरा/भाषा। इंग्लैंड की पूर्व विकेटकीपर और गुजरात जायंट्स की क्षेत्ररक्षक कोच सारा टेलर ने भारत को आगामी पुरुष टी20 विश्व कप के खिताब का मजबूत दावेदार मानते हुए कहा कि सभी प्रारूपों में जबरदस्त पावर-हिटिंग ने भारत को विश्व क्रिकेट में एक मजबूत ताकत बना दिया है। उन्होंने कहा कि महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) ने महिला क्रिकेट के विकास को तेज किया है।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ डब्ल्यूपीएल एलिमिनेटर से पहले टेलर ने सोमवार को यहां कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां मौजूदा पीढ़ी पारंपरिक कलात्मक बल्लेबाजी शैली में ताकत भी जोड़ रही है।

टेलर ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, '' वे सही दिशा में बढ़ रही हैं और पिछले साल की तुलना में उन्होंने काफी सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ी जिस सहजता से बड़े शॉट खेल रहे हैं, वह अविश्वसनीय है। पांच साल में भारत बिल्कुल उड़ान भर रहा होगा। टेलर ने कहा कि अब ऐसे खिलाड़ी भी लगातार बाउंड्री पार कर रहे हैं, जिनकी कद-काठी बहुत मजबूत नहीं है। कुछ साल पहले हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता था। उन्होंने कहा, आपके पास छोटी कद-काठी की युवा लड़कियां हैं, जो आसानी से छक्के लगा रही हैं। पहले यह ताकत खेल का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने डब्ल्यूपीएल की भूमिका पर कहा कि इस लीग ने युवा भारतीय खिलाड़ियों को ब्रिटेन में होने वाले महिला टी20 विश्व कप से पहले अहम अनुभव दिया है। उन्होंने कहा, ''उन्हें दूधिया रोशनी में खेलते हुए करीबी मुकाबलों का अनुभव मिल रहा है। वे दुनिया की कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए यह काफी चीजें सीख रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''विश्व कप में जाने से पहले इन लड़कियों को कोई परेशानी नहीं होगी। वे यह सब कर चुकी हैं।''

टेलर ने अनुष्का शर्मा जैसी युवा खिलाड़ियों को भविष्य का सितारा बताते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में सीखने की ललक ही उनके तेजी से सुधार की वजह है। उन्होंने कहा, ''वे सीखना चाहती हैं और यही सबसे खूबसूरत बात है। वे सिर्फ बेहतर ही होती जाएंगी।

सुविचार

कोशिश आखरी सांस तक करनी चाहिए मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही कीमती है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अपने ही चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान

आतंकवाद की आग भड़काने वाला पाकिस्तान अब खुद उससे झुलस रहा है। बलूचिस्तान में दर्जनों अलगाववादियों और सुरक्षा बलों के जवानों की मौत के बाद यह हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि पाकिस्तान अंदर से बहुत कमजोर हो गया है। अगर अलगाववाद की यह लहर और मजबूत हुई तो इस पड़ोसी देश का अस्तित्व गंभीर संकट में पड़ सकता है। इसका नक्शा भी बदल सकता है। बलूचिस्तान की घटना उन संगठनों और लोगों के लिए सबक है, जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर शांति और सद्भाव को खतरे में डालते हैं। पाक ने अपने किसी प्रांत के साथ इन्साफ नहीं किया। बलूचिस्तान में आजादी की मुहिम चल रही है, सिंध भी धधक रहा है। केपीके में आए दिन धमाके होते रहते हैं। पहले, पंजाब को बहुत सुरक्षित माना जाता था। वहां भी कट्टरपंथ जड़ें जमा चुका है। पाकिस्तान की इस हालत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसकी फौज है। सैन्य अधिकारियों ने लूट मचाकर अपने खजाने भरे और जनता को जरूरत की छोटी-छोटी चीजों के लिए तरसाते रहे। बलूचिस्तान में गैस और खनिजों के बड़े भंडार हैं। संसाधनों की दृष्टि से इतना संपन्न होने के बावजूद यह प्रांत बदहाल है। इसके गैस भंडार से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे शहरों में लोग खाना बनाते हैं, जबकि आम बलूच लकड़ी का चूल्हा फूंकने को मजबूर है। पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में उद्योग-धंधों को पनपने ही नहीं दिया, लेकिन उसके अधिकारी वहां जमकर मलाई खा रहे हैं। हर महीने हजारों लीटर ईरानी तेल की तस्करी होती है, जिसमें अधिकारियों का हिस्सा होता है।

जब हर तरफ से बलूचों को इतना दबाया जाएगा तो वे अपना हक मांगने के लिए क्यों नहीं खड़े होंगे? उन्होंने हाल के वर्षों में कई घातक हमले किए हैं। ताजा हमला बहुत बड़ी तैयारी का नतीजा है। बलूचों ने क्वेटा, सिबी, ग्वादर, नोशकी, पसनी में पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी।

जब हर तरफ से बलूचों को इतना दबाया जाएगा तो वे अपना हक मांगने के लिए क्यों नहीं खड़े होंगे? उन्होंने हाल के वर्षों में कई घातक हमले किए हैं। ताजा हमला बहुत बड़ी तैयारी का नतीजा है। बलूचों ने क्वेटा, सिबी, ग्वादर, नोशकी, पसनी में पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। उन्होंने बैंक शाखाओं और महत्त्वपूर्ण इमारतों पर कब्जे कर लिए थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसे आखिरी हमला नहीं समझना चाहिए। बलूच फैसला कर चुके हैं कि वे पाकिस्तान के झंडे तले नहीं रहेंगे। वे जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह स्थिति रातोंरात पैदा नहीं हुई है। पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिशों में दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। इस पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए। अगर यह राशि अपने नागरिकों की भलाई पर खर्च करते तो हालात ऐसे न होते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें मित्र देशों से वित्तीय सहायता मांगते हुए अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। वहां सेना प्रमुख हो या प्रधानमंत्री, दोनों इसी काम में लगे रहते हैं। शहबाज शरीफ के शब्दों- 'जब आप ऋण लेने जाते हैं तो आपको अपने आत्मसम्मान की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको समझौता करना पड़ता है ... कभी-कभी अनुचित मांगें सामने आ सकती हैं और आपको उन्हें पूरा करना पड़ सकता है, भले ही उन्हें पूरा करने का कोई कारण न हो।'- से पता चलता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी मानसिकता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस चक्रव्यूह से निकलने का सिर्फ एक तरीका है- आतंकवाद का रास्ता छोड़ें, भारत के साथ संबंधों को सुधारें। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो भविष्य में उसके अस्तित्व पर संकट आना तय है।

ट्वीटर टॉक

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे देवतुल्य नागरिकों से आत्मीय भेंट कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

-भजनलाल शर्मा

सामाजिक चेतना में राष्ट्रधर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए आजीवन तप करने वाले श्री क्षत्रिय युवक संघ के चतुर्थ प्रमुख पूज्य श्री भगवान सिंह जी रोलसाबसर की 82वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ भाव से श्रद्धासुमन अर्पित हैं। उनके शब्दों में गहरी प्रेरणा थी और व्यवहार में सहज उदारता।

-गजेन्द्रसिंह शेखावत

सामाजिक चेतना में राष्ट्रधर्म को प्रतिष्ठित करने हेतु आजीवन तप और समर्पण करने वाले श्री क्षत्रिय युवक संघ के चतुर्थ प्रमुख, पूज्य भगवान सिंह रोलसाबसर की 82वीं जन्म जयंती पर आज संघ शक्ति भवन, झोटवाड़ा में पूज्य रोलसाबसर को श्रद्धासुमन अर्पित कर सादर नमन किया।

-दिया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

धरती पर स्वर्ग-नरक

एक सूफी संत से कुछ लोगों ने पूछा कि जन्नत (स्वर्ग) और दोज़ख़ (नरक) क्या है। सूफी संत उन्हें अगले दिन एक शिकारी के पास ले गए। वह शिकारी बहुत से जानवरों का शिकार कर उन्हें मार चुका था। सूफी संत ने कहा, 'यह दोज़ख़ का मंजर है। उसके लिए इस दुनिया में भी दोज़ख़ है और मरने के बाद भी।' इसके बाद वे एक फ़क़ीर के पास गए, जो जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। वह सुकून और आनंद से भरा हुआ था। सूफी संत ने कहा, 'इस फ़क़ीर ने आने वाले सुख के लिए आज के सुख का त्याग किया है, इसे जन्नत मिलना निश्चित है।' अंत में वे एक साधारण व्यक्ति के घर में गए, जहां आपसी प्रेम, मेहनत, दान और सादगी थी। सूफी संत ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए यहां भी जन्नत है और वहां भी जन्नत।

सामयिक

नारी देह, नारी अधिकार: माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

ललित गर्ग
मोबाइल : 9811051133

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता।

विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है।

कानून और आदेश दिशा दिखा सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक शुरुआत है, मंज़िल नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनाते हैं।

न्यायालय ने शिक्षा को एक 'मल्टीप्लायर राइट' बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके।

माहवारी स्वच्छता केवल पैड उपलब्ध कराने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ जुड़ा है स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्णकृसही जानकारी। आज भी अनेक लड़कियाँ पहली माहवारी के समय भय, भ्रम और अपराधबोध से घिर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से कोई वैज्ञानिक और संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में यदि स्वास्थ्य शिक्षा को गंभीरता से लागू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह डर और संकोच स्वतः समाप्त हो सकता है। यह भी सच है कि माहवारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी पुरुषों की भूमिका को भी प्रश्नों के घेरे में लाती है। जब तक पुरुष-चाहे वे पिता हों, शिक्षक हों, प्रशासक हों या नीति-निर्माता, इस विषय को केवल महिलाओं का मामला मानकर किनारे करते रहेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने समाज और खासकर पुरुषों को संवेदनशील बनने का अवसर दिया है। जागरूकता का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि पुरुषों को सहृदय और जिम्मेदार बनाना भी है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी से जुड़ी चुनौतियाँ और भी गंभीर हैं। वहाँ आज भी कपड़े, राख या अस्वच्छ साधनों का उपयोग आम है, जिससे संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सरकारी योजनाएँ और गैर-सरकारी प्रयास मौजूद हैं, परंतु उनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यदि ईमानदारी से लागू होता है, तो यह नीति और जमीन के बीच की खाई को पाटने में सहायक हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि माहवारी स्वच्छता को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर महिला अधिकारों के व्यापक ढाँचे में देखा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार-तीनों इस विषय से सीधे जुड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लड़की केवल इसलिए स्कूल न जा सके क्योंकि उसके पास सेनेटरी पैड नहीं हैं, वह व्यवस्था संविधान की आत्मा के विपरीत है। इसलिए यह फैसला सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूती देता है।

आज भारत नए प्रवेश के साथ आगे बढ़ने की बात करता है-डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है। किंतु यदि इस विकास की गाथा में महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताएँ और सम्मान शामिल नहीं हैं, तो यह प्रगति खोखली सिद्ध होगी। वास्तविक विकास वही है जो सबसे कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का साहस रखे। माहवारी जैसे विषय पर खुली चर्चा उसी साहस का प्रतीक है। समाज में जन-जागृति लाना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कानून और आदेश दिशा दिखा सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक शुरुआत है, मंज़िल नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनाते हैं। यदि हम सचमुच एक समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय भारत का निर्माण चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ नया भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को विकास के केंद्र में रखना ही होगा। माहवारी से मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक सुविधा नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान होती है।

नजरिया

हिमालय क्षेत्र की बर्बादी से नेताओं को नहीं कोई सरोकार

योगेंद्र योगी

देश के राजनीतिक दल देश के लोगों के लिए कितने गैरजिम्मेदार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में शोध पर आधारित दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी के बारे में किसी ने चिंता तक जाहिर नहीं की। इन रिपोर्टों में सर्दी के मौसम में हिमालय क्षेत्र जंगलों में लगने वाली आग के कारण और भूस्खलन के नए केंद्रों की जानकारी दी गई है। दरअसल ऐसी जानकारियों को गंभीरता से लेने पर राजनीतिक दलों के वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। यही वजह है अत्यंत संवेदनशील और आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में जगह नहीं पाते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1,756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। यह संख्या महाराष्ट्र (1,028), कर्नाटक (924), मध्य प्रदेश (868) और छत्तीसगढ़ (862) जैसे उन राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से जंगल में आग के मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। आमतौर पर दिसंबर जंगल में आग के लिहाज से सबसे शांत महीना माना जाता है, लेकिन पिछले तीन सालों में उत्तराखंड के लिए यह धारणा गलत साबित हुई है। दिसंबर में उत्तराखंड में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जंगल की जमीन में नमी का लेवल बहुत कम है। उत्तराखंड की तरह, हिमाचल में भी पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह से कोई बारिश नहीं हुई थी।

इसी तरह, कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में भी बर्फबारी लगभग न के बराबर हुई है। इस वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। देहरादून में तो कई बार यह इंडेक्स 300 के पार जा चुका है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की ओर से कराए गए एक अध्ययन ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि पर्यावरण प्रदूषण में फॉरेस्ट फायर की भूमिका 15 से 20 प्रतिशत तक है, जो कि बेहद गंभीर आंकड़ा है। उत्तराखंड का हिमालयी भूगोल, जलवायु परिवर्तन और तेज विकास की दौड़ मिलकर राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में राज्य में तेज गति से सड़क निर्माण और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इसका परिणाम यह निकला कि चारधाम यात्रा रूट के आसपास लगभग 100 नए भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए। पहले से मौजूद संवेदनशील जोन भी और अधिक खतरनाक हो गए हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन तेजी से निर्माण कार्यों ने पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया है। सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की गई, भारी मशीनरी का उपयोग हुआ, जंगलों का व्यापक कटान किया गया। इन सभी वजहों से पुराने भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हुए और नए भूस्खलन क्षेत्र भी बन गए। उत्तराखंड के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर करीब 400 भूस्खलन स्थल चिन्हित किए गए हैं।

उत्तराखंड में मानसून सीजन में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। साल 2025 के मानसून सीजन में अब तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हुई है। उत्तराखंड में 2016 से 25 तक प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। पिछले 11 वर्षों में 27,197 प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें अतिवृष्टि और भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख हैं। साल 2025 में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुईं, जिसमें 720 लोगों की मौत और 1207 लोग घायल हुए थे। इन 11 सालों के आंकड़े में केदारनाथ की साल 2013 में 16 और 17 जून को आई प्राकृतिक आपदा के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। उस दौरान अकेले केदारनाथ में ही 4400 से ज्यादा लोग या तो लापता हो गए थे या फिर मारे गए थे।

हिंदुकुश हिमालय का इलाका भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी 11 बड़ी नदियां बहती हैं। वसंत के महीने में बर्फ पिघलने से ही इन नदियों को पानी मिलता है। लगभग 17 प्रतिशत आबादी पीने के पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। इसी पानी का उपयोग सिंचाई और हाइड्रोपावर के लिए भी किया जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के तापमान में वैश्विक औसत से 0.74ओउ अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साल 2003 से 2020 तक हिमालय के अधिकांश हिस्सों में बर्फ से घिरे इलाकों में गिरावट देखी गई। पहले यहां औसतन 102 दिनों तक बर्फ रहती थी। अब हर दस साल में पांच दिन कम हो रहे हैं।

भारत के मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभों के कमजोर होने से पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में न के बराबर बर्फ गिरी। गढ़वाल में इस साल जनवरी में बर्फबारी का अभाव देखा गया। ऐसा पिछले 40 सालों में पहली बार हुआ है। कम हिमपात के चलते जटामांसी और कुटकी जैसी महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ीबूटियां विलुप्त हो रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में स्नो ड्रॉट या 'बर्फ का सूखा' जैसी स्थिति बन रही है। विशेष रूप से 3,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह प्रभाव सबसे अधिक देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में बेलगाम विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल एक दिन नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाबतलब किया। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल में भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं मानव निर्मित हैं। बिना वैज्ञानिक अध्ययन के फोर लेन रोड बन रहे हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उनके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। सिर्फ राजस्व कमाना सब कुछ नहीं। पर्यावरण के विनाश की कीमत पर ऐसी कमाई हिमाचल के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। आश्चर्य की बात यह है कि राजनीतिक दलों को जो काम करना चाहिए उसे सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। अभी भी वक्त है हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण की यदि सुध नहीं ली गई कि तो भविष्य में ज्यादा गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। (साभार : प्रभा साक्षी)

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. **Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

बांग्लादेश की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामलों में शेख हसीना को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई

ढाका/भाषा। बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सरकारी आवास परियोजना में भूमि आवंटन से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में सोमवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ढाका की विशेष अदालत ने 79 वर्षीय शेख हसीना को सरकारी पद का गलत इस्तेमाल कर पुरबाचोल स्थित राजधानी उन्नयन कर्तृपक्ष (राजुक) न्यू टाउन परियोजना में अपनी भतीजी एवं ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद व वहां की पूर्व मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक सहित अन्य लोगों को आवासीय भूखंड दिलाने के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश रोबी-उल आलम ने इसी मामले में शेख हसीना की दो भतीजियों और एक भतीजे को भी अलग-अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई।सिद्दीक की छोटी बहन आजमान सिद्दीक और भाई रदवान मुजीब सिद्दीक बॉबी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अपदस्थ प्रधानमंत्री और उनके रिश्तेदारों को यह सजा उनकी अनुपस्थिति में हुई सुनवाई के बाद दी गई। मामले के 16 आरोपियों में से केवल एक, भूखंड आवंटित करने वाली संस्था राजुक के वरिष्ठ अधिकारी खुर्शीद आलम पर ही व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चला और फैसले के समय वह अदालत में मौजूद थे। मामले के अन्य आरोपियों को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई, जिनमें आवास मंत्रालय के पूर्व कनिष्ठ मंत्री, मंत्रालय के पूर्व सचिव, राजुक के पूर्व अध्यक्ष और संस्था के अन्य अधिकारी शामिल हैं। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा, आरोपियों का मुकदमा इस आधार पर नहीं रोका गया कि वे देश से बाहर मौजूद हैं।'' इस बीच, अब भंग हो चुकी हसीना की अवामी लीग ने इन सजाओं को पहले निर्धारित और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा बनाए गए झूठे मुकदमे करार दिया। पार्टी पहले ही इन आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बता चुकी है।

वहीं, ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक ने कहा कि ''पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक त्रुटिपूर्ण और हास्यास्पद जैसी थी।'' सिद्दीक के हवाले से बीबीसी ने कहा, ''मैं इस पूरे घटनाक्रम को देखकर चकित हूं-डेढ़ साल से मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर भी मेरा बांग्लादेशी अधिकारियों से अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ।'' उन्होंने कहा, ''मुझे कोई समन नहीं भेजा गया, कोई आरोपपत्र नहीं है, मुझसे उनका कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ-मुझे ढूंढ़ना मुश्किल तो नहीं है, मैं सांसद हूं।''

पांच अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई थी और इसके बाद अंतरिम सरकार ने हसीना, उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए।

मुलाकात

ई दिल्ली में सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, साउथ एवेन्यू इलाके, नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मिलने जाती हुई।

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा शुभम लोनकर फरार

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा सेलेब्स को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले अभिनेता सलमान खान, कमीडियन कपिल शर्मा, और अब निर्देशक-निर्माता रोहित शेट्टी के साथ हुई घटना से हर कोई हैरान है। मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है और इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच को मामले में कई सबूत भी मिले हैं, जिनके आधार पर क्राइम ब्रांच का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड गैंगस्टर शुभम लोनकर घटना का मास्टरमाइंड है और उसी ने घटना की जिम्मेदारी भी ली है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए बताया कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में शुभम लोनकर का हाथ है और फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी फरार है और उसे लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गा शुभम लोनकर ने घटना की जिम्मेदारी भी ली थी और फायरिंग करने वाले आरोपियों को मदद भी मुहैया कराई थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी प्रारंभिक जांच में आरोपी शुभम लोनकर का नाम सामने आया था। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी का बयान दर्ज किया है और उनके घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है।

घटना निर्देशक के जुहू इलाके में स्थित नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर घटी थी, जहां रात 12 बजे के आस-पास अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे में लगी लेकिन गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ था।

निर्माता की कुर्सी पर वापस आई सौंदर्या रजनीकांत

मुंबई/एजेन्सी

तमिल सिनेमा की जानी-मानी हस्ती और अनुभवी फिल्म निर्माता सौंदर्या रजनीकांत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लंबे समय बाद वह फिल्म निर्माण की दुनिया में वापसी कर रही हैं। इस बीच उन्होंने एक इवेंट में बीते सालों की यादें, संघर्ष और नई शुरुआत की झलक साझा की। दरअसल, सौंदर्या रजनीकांत निर्देशक मदन की फिल्म 'विद लव' के प्री-रिलीज इवेंट में शामिल हुईं। वह इस फिल्म की निर्माता हैं। उन्होंने कहा, ''यह पल मेरे लिए सिर्फ एक फिल्मी इवेंट नहीं, बल्कि जीवन का भावुक क्षण है। मैंने निर्देशक वेंकट प्रभु को इस कार्यक्रम में आने के लिए फोन किया था। बातचीत के दौरान वेंकट प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि उनकी पिछली फिल्म 'गोवा' को रिलीज हुए पूरे सोलह साल हो चुके हैं।''

सौंदर्या ने बताया, '''गोवा' ही वह फिल्म थी, जिसके साथ मैंने निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए और लंबे समय तक मैं फिल्मों से दूर रही। जब वेंकट प्रभु ने 16 साल का जिक्र किया, तो वह पल मेरे लिए बेहद भावुक हो गया, क्योंकि इतने लंबे समय बाद फिर से निर्माता की भूमिका में लौटना बेहद खास होता है।'' उन्होंने मंच से कहा, ''इतने साल पहले मैंने मन ही मन यह ठान लिया था कि अगर कभी मैं दोबारा फिल्म निर्माण में लौटूंगी, तो एक ऐसी टीम के साथ लौटूंगी, जो दिल से काम करे, ईमानदार हो और जिसमें रचनात्मक ऊर्जा हो। आज फिल्म 'विद लव' की पूरी टीम को देखकर मुझे लगा कि मेरा वही सपना सच हो गया है।'' सौंदर्या ने बेहद भावुक अंदाज में कहा, ''मैं इस वापसी को लेकर बहुत खुश हूं, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, मेरे धैर्य, विश्वास और मेहनत की जीत है। इतने लंबे अंतराल के बाद इस तरह की टीम के साथ लौटना किसी वरदान से कम नहीं है।''

मुंबई में सोमवार को बॉलीवुड एक्टर इमरान खान और अवंतिका मलिक खान वैरायटी इंडिया की लॉन्च पार्टी के दौरान।

परीक्षा

वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पहला एग्जाम देने के बाद क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स एक एग्जाम सेंटर के बाहर हल्के-फुल्के पल बिताते हुए।

महंगे स्मार्टफोन की ओर बढ़ा रुझान, एप्पल की भारत में रिकॉर्ड 28 प्रतिशत मूल्य हिस्सेदारी

नई दिल्ली/भाषा। प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 28 प्रतिशत की अपनी अब तक की सबसे अधिक मूल्य हिस्सेदारी दर्ज की है। काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार यह उपलब्धि प्रीमियम उपकरणों के बढ़ते चलन के कारण संभव हुई है, जिसमें उपभोक्ता तेजी से महंगे उपकरण चुन रहे हैं।

रिपोर्ट में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया कि जहां बिक्री की संख्या में वृद्धि स्थिर है, वहीं बाजार का कुल बिक्री मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय खरीदार अब महंगे मॉडल ले रहे हैं।

काउंटरपॉइंट के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में भारत में एप्पल की मूल्य हिस्सेदारी 23 प्रतिशत थी। आईफोन 16 सीरीज की सफलता, आकर्षक वित्तपोषण योजनाओं और 'एक्सचेंज ऑफर' ने कंपनी को देश में अपनी सर्वोच्च मूल्य हिस्सेदारी तक पहुंचा दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया, ''त्योहारों के दौरान प्रचार और बिक्री चैनल के विस्तार ने राजस्व वृद्धि को सहारा दिया, जिससे एप्पल 2025 में मूल्य के मामले में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बाजार में शीर्ष पर रही। आईफोन-16 वर्ष 2025 में भारत में सबसे ज्यादा आयात किया जाने वाला मॉडल रहा।''

भारत का स्मार्टफोन बाजार 2025 में बिक्री की संख्या के मामले में एक प्रतिशत और मूल्य के मामले में आठ प्रतिशत की दर से बढ़ा। खुदरा बाजार में 2025 में कुल स्मार्टफोन बिक्री का 40 प्रतिशत हिस्सा वित्तपोषण (ईएमआई) के जरिये आया। तीस हजार रुपए से अधिक के प्रीमियम खंड में, लगभग दो-तिहाई खरीदारी वित्तपोषण के जरिए की गई, जो महंगे फोन खरीदने में ईएमआई की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग ने फोल्डेबल स्मार्टफोन खंड में अपना दबदबा बनाए रखा और 2025 में बिक्री की संख्या के लिहाज से 88 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। मोटोरोला बिक्री की संख्या के लिहाज से सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड रहा।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक के अनुसार, प्रीमियम खंड (30,000 रुपए से ऊपर) वर्ष 2025 में 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला खंड रहा।

हिरासत

पटना में सोमवर के पुलिस ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के सपोर्ट में पटना में 'जस्टिस मार्च' के दौरान पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया।

'कित्थे रह गया' पर आम्रपाली दुबे ने शेयर किया वीडियो

मुंबई/एजेन्सी

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और पोस्ट के जरिए अपने फैंस के दिलों में खास मौजूदगी रखती हैं। सोमवार को उन्होंने एक मजेदार वीडियो शेयर किया। दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर पंजाबी सॉन्ग 'कित्थे रह गया' काफी ट्रेंड कर रहा है। कई सेलेब्स और सोशल मीडिया यूजर्स, सेलेब्रिटी वीडियो बनाकर ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। ट्रेंड को फॉलो करते हुए अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी शानदार वीडियो बनाया है। वे गाने के बोल पर शानदार एक्सप्रेशन दे रही हैं और कैमरे के सामने गाने की लय के साथ चेहरे के भाव बदल-बदलकर लुत्फ उठा रही हैं। अभिनेत्री का ये अंदाज काफी आकर्षक लग रहा है और उन्होंने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर स्माइली इमोजी से प्रतिक्रिया दी। फैंस को ये गाने काफी पसंद आ रहे हैं। गाने में आम्रपाली का अंदाज इतना नेचुरल लग रहा है कि वे इसे काफी एंजॉय कर रहे हैं।

गाना 'कित्थे रह गया' की बात करें तो इसे नीति मोहन ने अपनी मधुर आवाज में गाया, जबकि इसके लिरिक्स कुमार ने लिखे और संगीत अभिजीत वाघानी ने तैयार किया था। आम्रपाली की लोकप्रियता भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। वहीं, अभिनेत्री भी अपने प्रशंसकों के लिए अक्सर जिंदगी से जुड़े अपडेट शेयर करती हैं। आम्रपाली अभिनय के साथ-साथ संगीत में भी हाथ आजमाती रहती हैं।

अभिनेत्री आम्रपाली अभी फिल्म 'माई से मिला द मैया वैष्णो देवी' की शूटिंग में व्यस्त हैं। अब वे जल्द ही फिल्म 'सास बहू यमराज' में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन संजय श्रीवास्तव ने किया है और इसके निर्माता रोशन सिंह हैं। फिल्म में आम्रपाली दुबे और विक्रांत सिंह के अलावा समर्थ चतुर्वेदी, अयाज खान, श्रद्धा नवल, विद्या सिंह, साहिल सिद्दीकी, रितु चौहान और अवधेश मुखिया सहित कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं : शुभांगी अत्रे

मुंबई/एजेन्सी

टेलीविजन की मशहूर शुभांगी अत्रे इन दिनों आगामी फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच अभिनेत्री ने इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। शुभांगी अत्रे ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अभिनेत्री ने हाल ही में बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉपुलर पॉडकास्ट 'ऑनेस्टली, व्हाई नॉट?' में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शिरकत की थी। इस शो में होस्ट ने अभिनेत्री से मनोरंजन जगत में दोस्ती को लेकर सवाल किए। होस्ट ने पूछा था कि क्या आपने कभी इंटरव्यू में अपने को-स्टार्स के साथ सबसे अच्छे दोस्त होने को लेकर झूठ बोला है? इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा, देखिए, यहां पर कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि यहां पर लोगों में कॉम्पीटिशन और एक दूसरे को लेकर इंसीक्योरिटी बहुत ज्यादा है। जब एक शो चलता है, तब आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस शो से निकलते हैं, वो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। फिर आप अपनी जिंदगी की एक नई यात्रा शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि एक एक्टर होने की सबसे अच्छी बात ये है कि आप खुद को लगातार खोजते और समझते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए यहां बेस्ट फ्रेंड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हां, इतना जरूर है कि जब तक हम साथ काम करते हैं, तब हम एक परिवार की तरह रहते हैं।इसके बाद होस्ट ने पूछा, आपके साथ सेट पर कभी ऐसा हुआ है कि सीन करने के बाद आपकी किसी के साथ नोकझोंक या लड़ाई हो गई और फिर से उन्हीं के साथ सीन करना पड़ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे करना ही नहीं है? इस सवाल का जवाब शुभांगी अत्रे ने हंसते हुए दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने काम को काफी पसंद करती हैं और जब किरदार में रहती हैं तो वे सब भूल जाती हैं। उन्होंने कहा, नोकझोक तो हुई है पर काम ही नहीं करना ये कभी नहीं हुआ है और जब मैं अपने किरदार में रहती हूं तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मुझे अपना काम बहुत पसंद है और मैं इसे पूरे मन से मजे लेकर करती हूं।

दिल्ली में खुला अनुपम खेर का नया एक्टिंग स्कूल, कहा, राजधानी अब साहस और कला का घर बन गई

मुंबई/एजेन्सी

हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर सिनेमा में वर्सटाइल एक्टिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, लेकिन साथ ही पर्दे पर कुछ बड़े स्टार्स की प्रतिभा को निखार कर उन्हें करियर बनाने में मदद की। अभिनेता बीते 21 साल से मुंबई में अपना एक्टिंग स्कूल एक्टर्स प्रीपेयर्स चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के कलाकारों को सपनों की उड़ान देने के लिए नया एक्टिंग स्कूल दिल्ली में खोला है। अनुपम खेर ने दिल्ली के कलाकारों को अपने सपने बिना भय के जीने का नया मौका दिया है और 31 जनवरी को दिल्ली में नए एक्टिंग स्कूल का उद्घाटन किया है। अभिनेता नए एक्टिंग स्कूल की ओपनिंग से बहुत खुश हैं क्योंकि अब एक्टिंग में अपना करियर बनाने वाले युवाओं को मुंबई का रुख नहीं करना पड़ेगा। अनुपम खेर ने वीडियो शेयर कर कहा, राजधानी अब साहस और कला का घर बन गई है। एक ऐसी जगह जहां प्रतिभा को निखारा जाता है, कमजोरी ताकत बन जाती है, और सपनों को ईमानदारी और

अनुशासन के साथ संवारा जाता है। अगर आपके मन में कहीं क्या हो अगर? की आवाज़ गूंजती है, अगर एक्टिंग आपका वो सपना है जिसे आपने अब तक के लिए टाल रखा था, तो ये रहा आपका पल।

अभिनेता ने ये भी साफ किया कि उनके मुंबई के एक्टिंग स्कूल एक्टर्स प्रीपेयर्स ने दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, ऋतिक रोशन जैसे कई सुपरस्टारों को निखारा है। उन्होंने कहा, हमने दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, ऋतिक रोशन जैसे कई सुपरस्टारों को आशा, भय और अटूट सपने से भरे हुए हमारी कक्षाओं में आते देखा है, और फिर वे ऐसे अभिनेता बनकर निकले जिन्होंने विश्वास करने का साहस दिखाया और अपने अनूठे तरीके से सफलता की कहानियां गढ़ीं। अब मुंबई की तरह दिल्ली में भी कलाकारों की कला को निखारने के लिए अभिनेता ने सिनेमा के आने वाले कल की नींव रख दी है। अब दिल्ली में कला सांस लेगी और उन्हें अपने सपनों को काश कहकर पछतावे की आग में नहीं जलाना पड़ेगा। 31 जनवरी को अनुपम खेर ने 'खोसला का घोसला-2' के अपने कोस्टार बोमन ईरानी के साथ मिलकर एक्टिंग स्कूल का उद्घाटन किया और दिल्ली से कलाकारों से जुड़ने की अपील की।

आचार्य कुलबोधिसूरी के 50वें संयम वर्ष पर आयोजित 'संयम सर्वस्वम महोत्सव' सम्पन्न

संयम, संस्कार और साधना का विराट संगम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के चंद्रप्रभु जैन नया मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में जॉर्ज टाउन स्थित कणिका परमेश्वरी वुमेन्स कॉलेज परिसर में आयोजित त्रिदिवसीय संयम सर्वस्वम महोत्सव' का रविवार को भावपूर्ण समापन हुआ। गच्छाधिपति आचार्य भुवनभानु सूरीश्वरजी समुदाय के आचार्य कुलबोधिसूरीश्वरजी के 50वें संयम वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित इस महोत्सव के अंतिम दिन 'अहो! श्रामण्यम के अंतर्गत शरण मेरा रजोहरण' विषय पर सारगर्भित प्रवचन हुआ। धर्मसभा में पाठशाला के बच्चों की मनोहारी प्रस्तुति के साथ-साथ चेन्नई में दीक्षित श्रमण-श्रमणी भगवंतों के अभिभावकों का ऐतिहासिक सम्मान किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश मूथा ने अतिथियों का स्वागत किया।

आचार्यश्री के मंगल प्रवेश अवसर पर समर्पण एवं तहत्ति ग्रुप द्वारा सुवाक्यों के बैनर प्रदर्शित कर अक्षत-वधामना की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु वंदन से हुआ। आचार्य कुलबोधिसूरीश्वरजी ने कहा कि चरित्र धारण करना ही परमात्मा की सर्वोत्तम आज्ञा है। धर्मी व्यक्ति ने क्या छोड़ा, यह नहीं बल्कि उसने क्या पाया, यह अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन की प्रेरक बातें साझा करते हुए बताया कि संस्कारयुक्त वातावरण के कारण मात्र 9 वर्ष की आयु में दीक्षा, सत्संग से जीवन का धन्य बनना, संयम से जीवन का भव्य रूप, स्वाध्याय से नवजीवन की प्राप्ति और चारित्र पालन से जीवन को दिव्यता की ओर ले जाना, ये सभी उनके संयम पथ के अमूल्य सोपान हैं। उन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांत अहिंसा और अनेकांतवाद को विश्वशांति के लिए अपरिहार्य बताया।

आचार्यश्री ने अपने संयम जीवन में बीस हजार से अधिक श्लोकों का अभ्यास, संस्कृत-प्राकृत व्याकरण तथा 45 आगमों का अध्ययन किया है। विभिन्न धर्मों, पंथों और ग्रंथों का गहन अध्ययन उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनके संपूर्ण परिवार द्वारा दीक्षा लेकर महावीर पथ का अनुसरण करना विशेष प्रेरणास्पद है। इस अवसर पर सकल संघ ने घणु जीवों गुरुवर की सामूहिक स्तुति गाकर आचार्यश्री के संयम जीवन की मंगलकामनाएं अर्पित की।

कार्यक्रम में लाभार्थी परिवार, समर्पण एवं तहत्ति ग्रुप का सम्मान किया गया। चेन्नई में प्रथम बार एक ही मंच पर 180 मुमुक्षुओं के अभिभावकों का सत्कार विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इसी अवसर पर आचार्यश्री ने प्रिंस रत्नपुरी जैन संघ मंदिर प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त भी प्रदान किया। आचार्यश्री के जीवन-सफर पर आधारित विशेष निर्देशित फिल्म का प्रदर्शन हुआ।

कार्यक्रम में ट्रस्टी खिमराज बालर, तेजराज कोठारी, सुरेश कागरेचा, विमल एल. शाह, भरत जगानी, जयंतीलाल कोठारी, मदनलाल संघवी, नेमीचंद कामदार, विजयराज भंडारी, हीराचंद चौहान, आकाश जैन, किशोर छाजेड़ सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे। संपूर्ण कार्यक्रम के लाभार्थी हुलासचंद-प्रमोद चौरड़िया परिवार थे। स्वर-संवेदना की प्रस्तुति विराज शाह ने दी जबकि संगीत संयोजन हर्षित शाह एवं धीरज निबिजिया ने किया।

डीपीएच स्कूल में पूर्व विद्यार्थियों के स्नेह मिलन में ताजा हुई पुरानी यादें

पूर्व विद्यार्थियों ने शिक्षकों व कर्मचारियों का किया सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के अमोलकचंद चोपड़ा हिंदी बालक बस्ती, धनराज फूलचंद हिन्दी हाईस्कूल, पतासीबाई कन्या हिन्दी हाईस्कूल व हुक्मीचंद खींचा बाल निकेतन के पूर्व विद्यार्थियों का स्नेह मिलन 'बेक टू स्कूल' का आयोजन रविवार को विक्टोरिया लेआउट स्थित डीपीएच स्कूल में हुआ। इस कार्यक्रम में 97वर्षीय पूर्व छात्रा मदनबाई व इंग्लैंड से कार्यक्रम में शामिल होने आई पूर्व छात्रा व आई बैंक ऑफ न्यूयार्क की उपाध्यक्ष ममता बिष्ट मुख्य आकर्षण थीं। पूर्व विद्यार्थियों के मिलन में देश भर में अनेक कम्पनियों के शीर्ष पदों पर आसीन व व्यापार में सफलता प्राप्त करने वाले शामिल थे। इस स्नेह मिलन में पुरानी यादों को ताजा करने के उद्देश्य से उपस्थित 600 पूर्व विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए लट्टू, रस्सी कूद, साबुन के पानी से बने गुब्बारे जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोजन में भी टिफिन बॉक्स थीम पर भोजन की व्यवस्था थी। सभी पूर्व विद्यार्थियों ने अपने जमाने की शिक्षा पद्धति, दोस्तों, शिक्षकों व स्कूल कर्मचारियों को याद किया। उपस्थित जनों में से कईयों ने अपने अपने दोस्तों से 30-40 वर्ष बाद मुलाकात की तो खुशी उनकी आंखों से आंसूओं के रूप में छलक पड़ी। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा स्कूल-कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, शिक्षकों व कर्मचारियों का सम्मान कर उपहार दिए।

यह कार्यक्रम हिन्दी शिक्षा की गौरवपूर्ण परंपरा को पुनर्जीवित करने, पुरानी यादें ताजा करने तथा पूर्व विद्यार्थियों के बीच स्नेहपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का अनुपम अवसर साबित हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जय कोठारी (दुधेडिया), मुकेश फोलामुथा, निर्मल गुलेछा, गोवर्धनदास अग्रवाल, गौतम गोटावत, निर्मल बोहरा और स्नेह मिलन टीम का भरपूर प्रयास और योगदान रहा।

आध्यात्मिक ज्ञान से ही चेतना का निर्माण होता है : कमलेशमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के गुडवांचेरी एसएस जैन संघ के तत्वावधान में राष्ट्रसंत कमलमुनिजी कमलेश ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान के ग्रंथ को वैज्ञानिक ज्ञान को अनुसंधान के माध्यम से रिसर्च रिपोर्ट को स्कूली पाठ्यक्रम दूरदर्शन और प्रचार माध्यमों के माध्यम से जनता के बीच प्रस्तुत किया जाए वह सर्व मान्य होगा। सभी धर्म के ग्रंथ पंथ परंपरा उपासना पद्धति अलग-अलग होने से एक दूसरे की बात को एक दूसरे का स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना आने पर पूरे संसार में मास्क का प्रयोग किया क्योंकि विज्ञान और डॉक्टर का परामर्श था, पर यदि उसको धर्म के नज़ारे से देखते तो आधे लोग किनारा काट लेते हैं। मुनि कमलेशजी ने बताया कि ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक ज्ञान का एक शब्द भी तीन लोक की संपत्ति देकर विज्ञान प्राप्त नहीं करवा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही विश्व गुरु बनने का सौभाग्य हिंदुस्तान को मिला है। संत ने कहा कि सरकार को वर्तमान बजट में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार का बजट भी विशेष रूप से पास करना चाहिए था उसी से विश्व शांति आ सकती है ।

जैन संत ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही चेतना का निर्माण होता है। संस्कार और संस्कृति का ज्ञान होता है और चरित्र का निर्माण होता है। आज भी पूरा विश्व भारत की आध्यात्मिकता का लोहा मान रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि योग, मौन, ध्यान, साधना, उपासना पद्धति की क्रिया पर अनुसंधान की आवश्यकता है, जो तन को बीमारी से मुक्त करता है संस्कार से परिपूर्ण करता है आत्मा के उत्थान में योगदान देता है।

स्वाध्याय भवन में पूर्णिमा पक्खी पर्व जप,तप, स्वाध्यायपूर्वक मनाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के में साहुकारपेट के बेसिन वाटर वर्क्स स्ट्रीट पर स्थित स्वाध्याय भवन में माघ शुक्ल पूर्णिमा पर्व पर जिनवाणी पर अनुप्रेक्षा की गई। वरिष्ठ स्वाध्यायी वीरेन्द्र कांकरिया ने संतश्री गौतममुनि म.सा के प्रवचन 'स्वाधीनता में सुख और पराधीनता में होता दुःख' पर स्वाध्याय अनुप्रेक्षा की। स्वाध्यायी ने विभिन्न आगमों में वर्णित सूत्र,संदेशों व प्रेरणा भरी गाथाओं का उल्लेख करते हुए स्वाधीनता व पराधीनता पर विवेचन किया। उपस्थित जिज्ञासु स्वाध्यायीगण द्वारा रखी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ। नरेन्द्र कांकरिया ने जैन संकल्प सूत्र करवाया व नथमल दुगड़ ने सामूहिक नियम व प्रत्याख्यान करवाए।

इस प्रसंग पर उच्छबराज गांग ने उपवास के प्रत्याख्यान किए। स्वाध्यायी अशोक रांका ने मंगल पाठ प्रदान किया। पूर्णिमा पाक्षिक पर्व पर वरिष्ठ स्वाध्यायी बादलचन्द बागमार ने सायंकालीन प्रतिक्रमण करवाया। गुरु सुखसाता पाठ गौतमचन्द मुणोत ने करवाया।

प्रस्तावित सालासर मंदिर में संगीतमय सुन्दरकाण्ड पाठ का आयोजन

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के रांका कालोनी बिलेकहल्ली में निर्माणाधीन श्री सालासर बालाजी मंदिर के सभागार में माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को दोपहर 3 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम सालासर बालाजी के चित्र के समक्ष विशेष पूजा की गई। तत्पश्चात हरिकिशन सारड़ा व संजू राठी द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रमोद मुरारका, उपाध्यक्ष सतीश मित्तल, सचिव मनित सोमानी सहित लाभार्थी प्रमोद टांटिया परिवार, अमृत भोग के लाभार्थी अलका मित्तल परिवार सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

जीण माता मंगलपाठ

मैसूरु के एक सभागार में माँ जीण का मंगलपाठ का आयोजन किया गया। भजन गायिका स्वाति शर्मा ने जीण माता का मंगलपाठ किया,गायक हिमांशु मंत्री, अंकिता मंत्री और रामसुन्दर बगड़िया ने अपने मधुर भजनों से माँ को रिझाया। दीपक केडिया ने मंगलपाठ में सेवा देने के लिए बेंगलूरु के जीण माँ दीवाने ग्रुप के प्रति आभार जताया। सुनील मोदी ने व्यवस्था संभाली। इस मौके पर जीण माता के मैसूरु के भक्तों ने मंगलपाठ में बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

तेरापंथ कन्या मंडल का 'उपनिषद-3' कार्यक्रम सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। तेरापंथ कन्या मंडल द्वारा आयोजित 'उपनिषद-3' कार्यक्रम का समापन रविवार को मुनि डॉ. पुलकित कुमार जी के सान्निध्य में हुआ। कार्यक्रम में महिला मंडल की उपाध्यक्ष सुमित्रा बरड़िया, मंत्री सरिता छाजेड़, बरखा पुगलिया उपस्थित थीं। कन्या मंडल संयोजिका खुशी मांडोत और महिला मंडल की उपाध्यक्ष सुमित्रा बरड़िया ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अनेक ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक गतिविधियाँ अंताक्षरी, पिक एंड स्पीक, शनिवार सामायिक, निबंध से तीर्थंकरों के नाम खोजने की गतिविधि, दादा-दादी और पोतियों के गुणों का आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी दादा-दादियों को स्मृति-चिह्न स्वरूप फोटो फ्रेम भेंट किए गए।

प्रवचन में पुलकित कुमारजी ने कन्याओं को जीवन में प्रगति के लिए सहिष्णुता के साथ जीने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने आधुनिक एवं तकनीकी युग में भी अपने दादा-दादी के साथ समय बिताने का मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण किया गया। कन्या मंडल प्रभारी खुशी कोठारी ने धन्यवाद दिया। महिला मंडल अध्यक्ष महिमा पटावरी ने शुभकामनाएं दी। संचालन जानवी कावड़िया ने किया। इस कार्यक्रम में कुल 16 कन्याएँ एवं 40 दादा-दादी दम्पति उपस्थित थे।

पूरी श्रद्धा व आस्था से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयम्बटूर। स्थानीय विश्वकर्मा विकास संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वकर्मा जयंती महोत्सव धूमधाम से आरएस पुरम प्रिया कुंज में मनाया गया । कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र की स्थापना के साथ हुई। सभी समाज बंधुओं ने भगवान की आरती कर भोग अर्पण किया। कार्यक्रम के दौरान धर्माराम प्रजापत द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा के भजनों की प्रस्तुति दी गई जिसे सुनकर समाज के लोगों ने नाच गाकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम में आगामी विश्वकर्मा जयंती के लिए विभिन्न बोलिया लगाई गई, जिसमें उपस्थित जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाहर से आए समाज बंधुओं व अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष लिखमाराम, कोषाध्यक्ष किशोर, सचिव भूमेश, अशोक कुसिप, ओम माकड़, हितेश, तेगराज, नारायण, मोतीलाल जेपाराम, सुखदेव विश्वकर्मा आदि अनेक लोग उपस्थित थे।

रेलवे उपभोक्ता समिति के पूर्व सदस्यों ने डीआरएम से की मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु । भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता परामर्श परिषद के पूर्व सदस्य भरत पालरेचा, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के पूर्व सदस्य सिद्धार्थ बोहरा एवं कांठा प्रांत जैन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रमेश गुगलिया ने बेंगलूरु रेल मंडल प्रबंधक(डीआरएम) आशुतोष सिंह से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय बजट में दक्षिण पश्चिम रेलवे को मिली सौगात के लिए डीआरएम के माध्यम से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने बेंगलूरु से पुणे हाईस्पीड बुलेट कॉरिडोर की मांग की। साथ ही बजट में अपेक्षित बेंगलूरु से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई हेतु लंबे समय से लंबित सुपर फास्ट ट्रेन के शीघ्र संचालन का तथा ट्रेन नंबर 14805 यशवंतपुर बाड़मेर एक्सप्रेस को साप्ताहिक से रोजाना करने की पहले से लंबित मांग का पुनः अनुरोध किया। इस अलावा प्रतिनिधियों ने बेंगलूरु रेलवे डिविज़न से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में बेहतरी के लिए अनेक सुविधाओं की मांग की। डीआरएम ने यात्री सुविधाओं की मांगों को शीघ्र ही दुरस्त करवाने एवं लंबित मांगों पर रेलवे बोर्ड भेजने का यथा संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।

एक जिन्दादिल व्यक्ति थे अमृतराज तलेसरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के जाने माने मार्बल व ग्रेनाइट के सफल व्यवसायी अमृतराज तलेसरा का 30 जनवरी को अल्प अस्वस्थता के बाद निधन हो गया था। अमृतराज एक सुलझे हुए दिलखुश मिजाज के सौम्य व मिलनसार व्यक्ति थे। स्व. अमृतराज एक जिन्दादिल व्यक्ति थे, जो उनसे एक बार मिल लेता था उनका ही होकर रह जाता था। सादड़ी राणकपुर मूल के निवासी अमृतराज धर्म, समाजसेवा के कार्य में रुचि लेते थे। उन्होंने कई वर्षों तक कर्नाटक मार्बल एवं ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवाएं दी। स्व. अमृतराज को नई नई जगहों पर

घूमने का, अच्छी गाड़ी व अच्छे कपड़े पहने का शौक था। उनका एक गुण था कि वह किसी भी ग्राहक से दोस्ती बनाकर व्यापार करते थे ताकि ग्राहक को सहजता महसूस हो। 68 वर्षीय श्री अमृतराज दोस्तों के दोस्त थे। वे अपने पुत्र द्वय अक्षय व आयुष के साथ भी मित्रवत व्यवहार ही करते थे और व्यापार की बारीकियां बहुत ही प्रभावी ढंग से समझाते थे। परिणामस्वरूप आज अक्षय व आयुष ने 'फर्श' नामक ग्रेनाइट व मार्बल कम्पनी तथा इसके अलावा वेयरहाउसिंग, फार्मलेंड, इंडस्ट्रियल पार्क सहित अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। स्व. अमृतराज तलेसरा 'दक्षिण भारत राष्ट्रमत' दैनिक अखबार के भी परम हितैषी थे।

अमृतराजजी के अग्रज ललितकुमार, विजयराज व अनुज कांतिलाल गोड़वाड़ जैन महासभा में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। तलेसरा रांका पार्क जैन संघ, जीतो, गोड़वाड़ महासभा आदि अनेक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े थे। स्व. अमृतराजजी अपने पीछे धर्मपत्नी, दो पुत्र, एक पुत्री और पोते पोतियों व दोहते दोहतियों से भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.